घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 225- मंगलवार 16- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत-स्लोवाकिया ने संबंधों को दिया 'व्यापक साझेदारी' का दर्जा,दोनों देशों के बीच 11 समझौते

टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,15 जून 2026। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' का दर्जा देने का फैसला किया है। दोनों देशों ने इसके अलावा आतंकवाद-विरोधी संयुक्त कार्य समूह और वाणिज्य दूतावास संवाद की स्थापना की भी घोषणा की है। दोनों देशों के बीच ब्रातिस्लावा में 11 समझौता ज्ञापन और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने वाला आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कोसिसे तकनीकी विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में आईसीसीआर की पहली चेयर की स्थापित की जाएगी। श्रम प्रवासन,पर्यटन,विज्ञान,डिजिटल प्रौद्योगिकी,उच्च शिक्षा और अनुसंधान, ऑडियो-विजुअल निर्माण,क्वांटम संचार और महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुष, छात्र

विनिमय कार्यक्रम व छात्रवृत्तियों और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने सोमवार को ब्रातिस्लावा में आमने-सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश, रक्षा व सुरक्षा, टेक्नोलॉजी व इनोवेशन, अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा, शिक्षा व संस्कृति और टैलेंट मोबिलिटी व लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। इनमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत को स्लोवाकिया द्वारा दी गई एकजुटता और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री फिको को धन्यवाद दिया। यह आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मेजबान को आपसी सहमति से तय की गई तारीख पर भारत आने का निमंत्रण दिया। वार्ता से पूर्व आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री फिको के साथ स्लोवाकिया के बच्चों की बनाई पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी देखी। यह पंचतंत्र और जातक कथाओं से प्रेरित थीं। प्रवक्ता ने कहा कि ये कलाकृतियां भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि, इंडिया-ईयू, एफटीए को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए समझौते इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनाएंगे। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।

रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने 'लेटर ऑफ इंटेंट' साइन किया। इससे साझा विकास, साझा उत्पादन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं।

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बवाल

संस्थापक अभिजीत दीपके को युवकों ने जड़े थप्पड़....

जयपुर,15 जून 2026। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ युवकों ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर भारी हंगामा शुरू हो गया।

घटना के बाद अभिजीत दीपक के समर्थकों ने भी थप्पड़ मारने वाले दो युवकों की जमकर पिटाई की और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अभिजीत दीपके जैसे ही समर्थकों के कंधों पर सवार होकर शहीद स्मारक पर पहुंचे थे तब गेट में घुसते ही कुछ युवकों ने उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिए, जवाब में समर्थकों ने भी थप्पड़ मारने वाले युवकों की जमकर पिटाई की। वहीं, जयपुर

पुलिस ने थप्पड़ मारने के आरोप में चार यवकों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा प्रणाली में विसंगतियों के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन और जनसभा का आयोजन किया था। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य सूत्रधार अभिजीत दीपके इस सभा में युवाओं और छात्रों को संबोधित करने पहुंचे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ ही युवाओं ने काफी देर तक मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हल्ला बोल किया। दोपहर 3 बजे शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में युवाओं के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सब ने एक साथ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की। इधर युवाओं के आक्रोश को देखते हुए शहीद स्मारक के आसपास पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान कई जगह युवा आपस में भी उलझते हुए नजर आए।

अमेरिका-ईरान जंग खत्म करने पर राजी,19 जून को दस्तखत

होर्मुज फिर खुलेगा,ट्रम्प बोले- दुनिया के जहाजो इंजन चालू करो,तेल को बहने दो

नई दिल्ली,15 जून 2026। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा।

उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने लिखा, 'दुनिया के जहाजो, अपने इंजन चालू कर लो। तेल को बहने दो।' इधर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल की बैठक होगी।

ईरान ने दस्तखत करने से पहले 3 शर्तें रखीं

ईरान-अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि रूक्ष पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका-ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने तीन वादे पूरे करता है या नहीं। गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को तीन कदम उठाने होंगे- 1. नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, 2. युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना, 3. ईरान के फ्रीज्ड फंड जारी करना।

इजराइल का यूएस-ईरान शांति समझौते को मानने से इनकार...नेतन्याहू के मंत्री बोले- लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे,हम अमेरिका के गुलाम नहीं...

इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शाति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी कहा है कि,उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान,सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजराइली सेना अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगी। वहीं, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने पीस डील पर नाराजगी जताते हुए कहा, 'हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। इजराइल एक आजाद देश हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता।'

कांग्रेस ने अमेरिका-ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते का किया स्वागत

कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शाति समझौते का स्वागत किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भले ही इस समझौते की पूरी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सबको उम्मीद है कि दोनों देशों के साथ इजराइल भी इस अंतरिम समझौते का पालन करेंगे। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने सोमवार को एक्स पोस्ट में कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बिना किसी प्रतिबंध के फिर से खुलने से भारत को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद संरचनात्मक समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये चिंताएं पश्चिम एशिया में मौजूदा युद्ध से पहले की हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के सिर्फ दो दिन बाद शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि रुपया एक वर्ष से अधिक समय से काफी दबाव में है और डॉलर की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।

राम मंदिर दान घोटाला मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट...योगी सरकार ने गठित की एसआईटी

नई दिल्ली,15 जून 2026। अयोध्या के भव्य और ऐतिहासिक श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में कथित चोरी और वित्तीय वित्तीय गड़बड़ियों का गंभीर मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। इस संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मामले पर त्वरित सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत से विशेष गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील अनूप अवस्थी ने इस पूरे प्रकरण में न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में एक निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच कराने की पुरजोर मांग की है। सीजेआई ने अदालत कक्ष में मौजूद सभी अधिवक्ताओं से पुरजोर अनुरोध किया है कि वे कोर्ट रूम के भीतर किसी भी केस की मौखिक मेंशनिंग करने से पूरी तरह बचें। सीजेआई सूर्य कांत ने साफ शब्दों में कहा, 'मौखिक बहस की जगह पर आप कृपया अपनी बात का एक लिखित नोट जमा करें, इसके बाद हम खुद यह तय करेंगे कि मामले में क्या जरूरी है और क्या नहीं।' इस पूरे विवाद के राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ने से ठीक पहले, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि से संबंधित गंभीर आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष अनुरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों पर इस उच्च स्तरीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है।

उन्नाव में साधु हत्याकांड का मुख्य आरोपी इसराइल पुलिस एनकाउंटर में ढेर...

लखनऊ,15 जून 2026। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में साधु मिलनदास हत्याकांड के मुख्य आरोपी इसराइल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह के अनुसार, बांगरमऊ थाना पुलिस और एसओजी टीम आगरा एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि साधु हत्याकांड का आरोपी ताजपुर अंडरपास के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। फायरिंग के दौरान एक गोली उपनिरीक्षक की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि एसओजी के एक सिपाही के हाथ में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी...लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली,15 जून 2026। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सोमवार को ओडिशा के तट पर स्थित डॉ। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम) का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रदर्शन पर पैनी नजर रखी गई। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर द्वारा तैनात किए गए विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों से मिले डेटा के अनुसार,टेस्ट के सभी लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लिए गए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस

परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। उड़ान के दौरान मिसाइल के प्रणोदन, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम और वॉरहेड डिलीवरी जैसी बेहद महत्वपूर्ण तकनीकों का कड़े मानकों पर सत्यापन किया गया। डीआरडीओ द्वारा भारतीय उद्योगों की मजबूत भागीदारी के साथ विकसित की गई इस मिसाइल और इसके सभी सब-सिस्टम का सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत और एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक और बड़ा व ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की टीम और इसमें शामिल इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई दी। परीक्षण के दौरान रक्षा सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह सहित भारतीय नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

तेज प्रताप यादव का सनसनीखेज आरोप,कहा...'खान सर ने कराई रौशन आनंद के भाई प्रिंस की हत्या'

बिहार,15 जून 2026। बिहार के सबसे चर्चित शिक्षकों में शुमार फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के बीच जारी कानूनी जंग अब एक बेहद खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जेल में बंद रौशन आनंद के सगे भाई प्रिंस यादव की रविवार को नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस रहस्यमयी मौत के बाद बिहार की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस मामले में सीधे एंट्री मारते हुए खान सर उर्फ फैजल खान पर हत्या की साजिश रचने का बेहद गंभीर और सीधा आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने कहा हमें पूरा यकीन और

भरोसा है कि खान सर ने ही हत्या करवाई है । ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की हत्या पर तेज प्रताप यादव ने कहा - ये हत्या खान सर के द्वारा कराया गया है। ये क्लियर है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव रविवार को नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल के कमरे से बरामद किया गया।

मोहनजोदड़ो की 'डांसिंग गर्ल' पर नया विवाद!

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बदलाव पर इतिहासकार नाराज

नई दिल्ली,15 जून 2026। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक प्रतीकों में से एक, मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली कांसे की प्रसिद्ध 'नर्तकी की मूर्ति' को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा 9वीं की नई किताब में इस ऐतिहासिक मूर्ति की तस्वीर को इसके मूल स्वरूप से पूरी तरह बदलकर छापा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में प्रकाशित की गई नई तस्वीर में मूर्ति के धड़ वाले हिस्से को पूरी तरह से ढंक दिया गया है, जबकि इसका मूल स्वरूप बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही तस्वीर में मूर्ति के वास्तविक रंग-रूप में भी काफी बदलाव नजर आ रहा है। पिछले करीब 25 वर्षों से विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में इस कांस्य मूर्ति को उसके वास्तविक

और मूल रूप में ही बिना किसी बदलाव के छापा जाता रहा था, लेकिन अब इसके ऐतिहासिक स्वरूप में बदलाव किए जाने पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, नर्तकी की इस विवादित और परिवर्तित तस्वीर को कक्षा 9वीं की नई किताब 'मधुरिमा' के पहले अध्याय, जिसका शीर्षक 'हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स' है, में शामिल किया गया है। किताब में छपी इस नई कलाकृति में मूर्ति के कंधे से नीचे के पूरे हिस्से को कपड़ों जैसी आकृति से ढंक दिया गया है।

बीकानेर : ट्रक-कार की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत...

बीकानेर,15 जून 2026। राजस्थान के बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीजरल होटल के पास ट्रक और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर में हरियाणा के एक ही परिवार के छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दो वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना करीब दोपहर डेढ़ बजे हुई, जिसमें हरियाणा नंबर की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर परखच्चे उड़ गई। कार में कुल सात लोग सवार थे, जो बीकानेर के मुकाम स्थित बिश्नोई समाज के गुरु जम्भेश्वर के समाधि स्थल के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। सभी शवों को श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी में रखा गया है।

एनसीपीआई में शामिल होने के बाद तृणमूल के बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ी,सुदीप बंद्योपाध्याय को मिलेगी 'वाई' श्रेणी

कोलकाता,15 जून 2026। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। इस बीच वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, एनसीपीआई में शामिल हुए अन्य बागी सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत किए जाने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में बढ़ती गतिविधियों के बीच हावड़ा स्थित एनसीपीआई कार्यालय के बाहर भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती किए जाने की खबर है। सुरक्षा व्यवस्था में यह बदलाव उस समय किया गया है जब तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया है। सूत्रों के मुताबिक, बागी सांसदों ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर एनसीपीआई के साथ जुड़ने के अपने फैसले की जानकारी दी थी। इसके बाद यह राजनीतिक घटनाक्रम और तेज हो गया। रविवार शाम तक एनसीपीआई पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपेक्षाकृत कम चर्चित दल माना जाता था, लेकिन बड़ी संख्या में सांसदों के शामिल होने के बाद पार्टी अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में आ गई है। जानकारी के अनुसार,एनसीपीआई का मुख्य राजनीतिक फोकस

पश्चिम बंगाल,असम और त्रिपुरा पर रहेगा। वहीं, तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के बावजूद बागी सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन जारी रखने की संभावना जताई जा रही है। एनसीपीआई कोई व्यापक जनाधार वाला राजनीतिक दल नहीं माना जाता है। पार्टी ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं कर सकी थी। हालांकि, 20 सांसदों के शामिल होने के बाद पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। एनसीपीआई से जुड़े एक सोशल मीडिया पृष्ठ पर नए सदस्यों का स्वागत करते हुए दावा किया गया है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर पार्टी अब पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है।

संपादकीय

चढ़ावे की चोरी

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। सदियों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद बना यह मंदिर विश्व भर के हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि दान की राशि में हेराफेरी की बात सामने आते ही उच्चस्तरीय जांच का निर्णय क्यों नहीं लिया गया?

इस मामले में जिस प्रकार एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई,उससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। यह विचित्र है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की भनक सबसे पहले विपक्षी नेताओं को लगी और उनकी ओर से आवाज उठाने के बाद ही मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। इससे तो यही इंगित होता है कि दान में मिले धन के प्रबंधन की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। कम से कम अब तो ऐसा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यह समझना कठिन है कि चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इससे इन्कार क्यों किया कि इस तरह की कहीं कोई घटना हुई है? इसके उपरांत जब दान राशि की गिनती से जुड़े लोगों के ठिकानों से लाखों रुपये मिले,तब जाकर इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाई गई। इनमें से कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं,जिन्होंने महंगी संपत्ति खरीदी और अपने वैभव का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। इस सबको देखते हुए यह कहना कठिन है कि दान की राशि में हेराफेरी का सिलसिला पिछले कितने समय से चला आ रहा था। यह ठीक है कि अंततः ट्रस्ट के आग्रह पर एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है। यह जांच दल दानपात्रों के सुरक्षा प्रबंध के साथ राशि गिनने और उसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया जांचेगा,लेकिन उचित यह होगा कि यह दल उन कारणों की तह तक भी जाए,जिनके चलते आरंभ में ही चढ़ावे की राशि में हेराफेरी का पता नहीं चल सका।

किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि इतने प्रतिष्ठित मंदिर में पहले दिन से ही ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि दान में मिली पाई-पाई का रखरखाव सही तरीके से हो? किसी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि प्रारंभ में ही उस कक्ष में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, जिसमें दानपात्रों को खोला जाता था और फिर राशि की गिनती होती थी।

उचित यह होगा कि विशेष जांच दल अपनी छानबीन इस तरह करे कि सभी दोषी पकड़े जाएं और ट्रस्ट के जिन भी लोगों ने अपेक्षित जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया, उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्रद्धा का कोई भी केंद्र हो,वहां यदि भक्तों के दान की राशि के साथ किसी भी तरह की हेराफेरी होती है तो उनकी आस्था को गहरी चोट पहुंचती है।

भारत अब सिर्फ विकसित नहीं हो रहा,विश्व को विकसित कर रहा है

प्रो.आरके जैन 'अरिजीत',बड़वानी,मध्यप्रदेश

तकनीक की वैश्विक बिसात पर भारत अब मोहरा नहीं,चाल चलने वाला खिलाड़ी बनता दिख रहा है। फ्रांस के नीस में 14-16 जून 2026 को आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि भारत अब समाधान का उपभोक्ता नहीं,समाधान प्रदाता है,केवल एक वक्तव्य नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन की घोषणा थी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की उपस्थिति,120 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स,15 अग्रणी शिक्षण संस्थानों और सैकड़ों निवेशकों की भागीदारी ने इस दावे को मजबूती दी। यह वह क्षण था जब भारत ने दुनिया को जता दिया कि वह तकनीकी परिवर्तन का दर्शक नहीं,बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है।

भारत की तकनीकी उड़ान किसी एक घटना नहीं,वर्षों की तैयारी का परिणाम है। 'मेक इन इंडिया','स्टार्टअप इंडिया'और 'आत्मनिर्भर भारत' ने इसकी मजबूत नींव रखी। जो देश कभी तकनीक खरीदता था,वह आज समाधान विकसित कर दुनिया को दे रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शित 120 डीप-टेक कंपनियों के पास सामूहिक रूप से 1,500 से अधिक पेटेंट हैं और उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा पूंजी जुटाई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता,क्वांटम कंप्यूटिंग,सेमीकंडक्टर,जैव-प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा के अलावा स्वास्थ्य,जलवायु प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस, एग्रीटेक आदि 13 अग्रणी क्षेत्रों में भारतीय कंपनियाँ नई राह बना रही हैं। बढ़ते पेटेंट,निवेश और स्टार्टअप्स बताते हैं कि भारत अब केवल सेवा प्रदाता नहीं रहा। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत ऐसे तकनीकी मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो किफायती भी हैं और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकते हैं। यही बदलाव भारत को वैश्विक विकास की नई धुरी बना रहा है।

भारत-फ्रांस संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अब कूटनीति से आगे बढ़कर नवाचार,अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की साझेदारी में बदल रहे हैं। 'इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026' और विस्तारित रणनीतिक साझेदारी भविष्य की उसी रूपरेखा को रेखांकित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की निरंतर पहल ने दोनों देशों को स्वाभाविक सहयोगी बना दिया है। फ्रांस अब भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं,बल्कि तकनीकी सह-निर्माता के रूप में देख रहा है। यही सोच इस रिश्ते को पारंपरिक द्विपक्षीय सहयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और दूरगामी बनाती है।

भारत का उभरता तकनीकी सामर्थ्य कई पुराने शक्ति-केंद्रों के लिए चुनौती बन रहा है। कारण यह है कि वह तकनीक पर स्थापित एकाधिकार की दीवारों में दरार डाल रहा है। दशकों तक नवाचार कुछ देशों और कंपनियों के इर्द-गिर्द सिमटा रहा,लेकिन भारत अब अपनी अलग तकनीकी राह बना रहा है। एआई और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर बढ़ते नियंत्रण के बीच भारत-फ्रांस सहयोग बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है। सेमीकंडक्टर, उन्नत सामग्री और महत्वपूर्ण खनिजों में बढ़ती साझेदारी बता रही है कि भविष्य की तकनीकी आपूर्ति पर अब कुछ हाथों का वर्चस्व नहीं रहेगा। भारत का सॉल्व्ड इन इंडिया मॉडल धीरे-धीरे सॉल्यूशन फॉर द वर्ल्ड की अवधारणा में बदल रहा है।

भारत-फ्रांस सहयोग का सबसे मजबूत चेहरा अब रक्षा और रणनीतिक तकनीक में दिखता है। राफेल कार्यक्रम ने तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन को नई दिशा दी है। दोनों देश अब रक्षा खरीद से आगे बढ़कर साझा निर्माण और उन्नत अनुसंधान की राह पर हैं। स्कॉर्पीन पनडुब्बियों से लेकर समुद्री सुरक्षा तक और साइबर सुरक्षा से लेकर क्वांटम अनुसंधान तक, सहयोग के नए द्वार खुल रहे हैं। परमाणु ऊर्जा में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर चर्चा ऊर्जा सुरक्षा की नई संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। अंतरिक्ष, विज्ञान और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग यह स्पष्ट करता है कि यह रिश्ता अब भविष्य की तकनीकी सभ्यता गढ़ने की साझी परियोजना बन चुका है।

भारत की यह तकनीकी प्रगति 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को मजबूत आधार दे रही है। भारतीय स्टार्टअप अब केवल मुनाफा नहीं,बल्कि वास्तविक समाधान प्रस्तुत कर वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहे हैं। जलवायु संकट के लिए क्लाइमेट टेक, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार और वित्तीय समावेशन में फिनटेक भारत की उभरती ताकत बन चुके हैं। ग्लोबल साउथ के कई देश भारत के विकास मॉडल को अपनाने की दिशा में देख रहे हैं। अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतांत्रिक, विविध और खुले नवाचार पर आधारित तकनीकी मानववाद है, जो तकनीक को केवल शक्ति नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाता है। तकनीकी प्रगति की इस तेज़ दौड़ में चुनौतियाँ भी उतनी ही वास्तविक हैं। तकनीक हस्तांतरण की गति बढ़ाना,बौद्धिक संपदा की सुरक्षा मजबूत करना,कुशल मानव संसाधन तैयार करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना अभी भी प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में केवल महत्वाकांक्षा नहीं,बल्कि मजबूत संस्थागत ढांचा और निरंतर निवेश भी जरूरी है।

शिक्षा में एक नये युग एवं शैक्षिक क्रांति की आहट

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

आज पूरी दुनिया शिक्षा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ज्ञान का विस्तार तो अभूतपूर्व हुआ है,लेकिन जीवन मूल्यों का क्षरण भी उतनी ही तेजी से दिखाई देता है। विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सुविधासंपन्न बनाया है,लेकिन मानसिक तनाव,हिंसा,प्रतिस्पर्धा,नैतिक संकट और मानवीय संवेदनाओं के क्षय जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रश्न लगातार गूंज रहा है कि क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था वास्तव में मनुष्य का निर्माण कर रही है या केवल पेशेवर और उपभोक्तावादी समाज का निर्माण कर रही है? ऐसे समय में जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा द्वारा प्रारंभ की गई आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूल की योजना एक नई आशा, नई दृष्टि और नए शैक्षणिक दर्शन के रूप में सामने आई है। यह केवल विद्यालयों की स्थापना की योजना नहीं है, बल्कि शिक्षा को उसके मूल उद्देश्य से जो ने का एक महाअभियान है। महासभा ने देशभर में लगभग सौ विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राजस्थान के श्रीडूंगरगढ़,गंगाशहर और नोखा तथा गुजरात के भुज में विद्यालयों का निर्माण और शैक्षणिक गतिविधियां तीव्र गति से संचालित हैं। इन विद्यालयों की स्थापना के पीछे केवल आधुनिक शिक्षण संस्थान खड़ा करने की भावना नहीं है,बल्कि ऐसी शिक्षा संस्कृति विकसित करने का संकल्प है जो ज्ञान के साथ संस्कार, विज्ञान के साथ विवेक और सफलता के साथ संवेदनशीलता का समन्वय स्थापित कर सके।

तेरापंथ धर्मसंघ की शिक्षा-दृष्टि सदैव व्यापक,मानवीय और दूरदर्शी रही है। इस परंपरा में शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्ति का माध्यम नहीं माना गया, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास का आधार समझा गया है। तेरापंथ के आचार्यों ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाना है। यदि शिक्षा केवल बुद्धि को विकसित करे और हृदय को उपेक्षित छोड़ दे,तो वह अधूरी शिक्षा है। यदि वह ज्ञान तो दे लेकिन चरित्र न बनाए,तो वह समाज के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकती है। आचार्य श्री तुलसी ने इस आवश्यकता को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से नैतिकता को सामाजिक जीवन के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि व्यक्ति,समाज और राष्ट्र का वास्तविक विकास नैतिक आधार पर ही संभव है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए नैतिक पाठमाला और नैतिक शिक्षा परीक्षाओं का अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया। उस समय यह केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का अभियान था। लाखों विद्यार्थियों ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से सत्य,अहिंसा,अनुशासन, संयम,ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त की।

आचार्य महाप्रज्ञ ने इस विचारधारा को और अधिक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने जीवन विज्ञान के रूप में एक ऐसा शैक्षणिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें शिक्षा को शरीर,मन, भावना और चेतना के विकास से जोड़ा गया। जीवन विज्ञान ने विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में सफल होने की तैयारी नहीं दी,बल्कि तनावमुक्त जीवन,भावनात्मक संतुलन,आत्मानुशासन और सकारात्मक सोच की दिशा भी प्रदान की। आज जब दुनिया मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक शिक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है, तब यह अनुभव होता है कि जीवन विज्ञान जैसी अवधारणाएं अपने समय से बहुत आगे की सोच थीं। आचार्य महाश्रमण ने इस समूची परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। उनका व्यक्तित्व ज्ञान,साधना,अनुशासन,अहिंसा और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय है। उनकी दृष्टि में शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक सीमित नहीं रह सकती। उसे मनुष्य के भीतर छिपी नैतिक, आध्यात्मिक और मानवीय संभावनाओं को भी जागृत करना होगा। इसी कारण उनके नाम पर स्थापित आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूल केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान नहीं,बल्कि जीवन-दृष्टि देने वाले केंद्र बनने की क्षमता रखते हैं।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूल का मूल मंत्र-ज्ञान,मूल्य और चरित्र है जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। आज अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में ज्ञान और कौशल पर तो पर्याप्त ध्यान दिया जाता है,लेकिन मूल्य और चरित्र का पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देता है। परिणामस्वरूप समाज में बौद्धिक प्रगति तो होती है, परंतु नैतिक और मानवीय संकट भी बढ़ते जाते हैं। आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूल इस असंतुलन को दूर करने का एक सार्थक एवं प्रभावी प्रयास साबित होगा। यहां शिक्षा का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं,बल्कि ज्ञान को विवेक में और विवेक को चरित्र में रूपांतरित करना है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 भी इसी प्रकार की समग्र शिक्षा की आवश्यकता पर बल देती है। नई शिक्षा नीति में बहुआयामी विकास, जीवन कौशल, भारतीय ज्ञान परंपरा,मूल्य आधारित शिक्षा और समग्र व्यक्तित्व निर्माण को विशेष महत्व दिया गया है। किंतु किसी भी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे व्यवहार में उतारने वाले संस्थान कितने सक्षम हैं। आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूल इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति के जीवंत और प्रभावी मॉडल बन सकते हैं। यहां आधुनिक पाठ्यक्रम,वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी के साथ-साथ नैतिकता, आत्मानुशासन,सह-अस्तित्व और आध्यात्मिक चेतना को भी समान महत्व दिया जाता है।

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष और प्रख्यात उद्योगपति महेंद्र नाहटा के अनुसार इस परियोजना को महासभा की प्रमुख शैक्षणिक गतिविधि के रूप में विकसित किया है। इन स्कूलों के उद्देश्य एवं उनकी दूरदृष्टि इस योजना को सामान्य विद्यालय परियोजना से कहीं अधिक व्यापक बनाती है। नाहटा का विश्वास है कि आने वाले समय में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता,स्वचालन और डिजिटल तकनीक के युग में मशीनें अनेक कार्य कर सकेंगी,लेकिन करुणा, संवेदनशीलता,नैतिक निर्णय,मानवीय संबंध और आत्मिक संतुलन जैसे गुण केवल मनुष्य ही विकसित कर सकता है। इसलिए शिक्षा को मस्तिष्क के साथ-साथ हृदय और आत्मा को भी शिक्षित करना होगा। महेंद्र नाहटा का यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये विद्यालय भारत की नई शिक्षा नीति को आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने का माध्यम बन सकते हैं। यहां आध्यात्मिकता का अर्थ किसी धार्मिक संकीर्णता से नहीं है,बल्कि आत्म-जागरूकता,नैतिकता,सहिष्णुता,मानवीय एकता और आंतरिक संतुलन से है। यह दृष्टिकोण आज के वैश्विक समाज की भी आवश्यकता है,क्योंकि विश्व के अनेक विकसित देशों में शिक्षा सुधार की चर्चाओं का केंद्र मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक उत्तरदायित्व और मूल्य आधारित जीवन बनता जा रहा है। आज शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह विद्यार्थियों को सफल तो बना रही है, लेकिन संतुष्ट नहीं; बुद्धिमान तो बना रही है, लेकिन संवेदनशील नहीं; सक्षम तो बना रही है, लेकिन चरित्रवान नहीं। परिणामस्वरूप समाज में तनाव,अवसाद,हिंसा, असहिष्णुता और सामाजिक विघटन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में शिक्षा के ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो मनुष्य को केवल प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं,बल्कि जीवन के लिए तैयार करे। जो उसे केवल करियर नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य भी प्रदान करे। जो उसे केवल कमाना नहीं,बल्कि जीना भी सिखाए। आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। यहां विज्ञान और अध्यात्म,आधुनिकता और संस्कृति, तकनीक और नैतिकता,प्रतिस्पर्धा और सहयोग,सफलता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। यह दृष्टिकोण भविष्य की शिक्षा का आधार बन सकता है। दुनिया भर में आज ऐसी शिक्षा की खोज हो रही है जो विद्यार्थियों को केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि विवेकवान और उत्तरदायी नागरिक भी बना सके। भारतीय शिक्षा परंपरा सदियों से इसी आदर्श की पक्षधर रही है। प्राचीन गुरुकुलों से लेकर आधुनिक आध्यात्मिक चिंतन तक, भारतीय दृष्टि ने शिक्षा को मनुष्य के समग्र विकास का माध्यम माना है।

यदि आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूलों की यह योजना अपने निर्धारित स्वरूप में विकसित होकर आगे बढ़ती है,तो यह केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं,बल्कि विश्व शिक्षा जगत के लिए भी एक प्रेरक मॉडल सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार कुछ देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है,उसी प्रकार भारत मूल्य-आधारित समग्र शिक्षा का वैश्विक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। यह मॉडल बताएगा कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि जीवन का निर्माण है; केवल सूचना का विस्तार नहीं, बल्कि चेतना का विकास है; केवल करियर की तैयारी नहीं, बल्कि चरित्र की साधना है। कवास्तव में आचार्य महाश्रमण इंटरनेशनल स्कूलों की स्थापना को केवल एक शैक्षणिक परियोजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह आचार्य तुलसी के अणुव्रत आंदोलन,आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन विज्ञान और आचार्य महाश्रमण की अहिंसामूलक एवं मानवीय दृष्टि का सृजनात्मक विस्तार है। यह शिक्षा को पुनः उसके मूल उद्देश्य से जो ने का प्रयास है। यह एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना है जहां विद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान नहीं होंगे, बल्कि मानवता के श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करने वाले केंद्र होंगे। यदि यह सपना साकार होता है तो न केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी,बल्कि विश्व को भी शिक्षा का एक ऐसा मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक मॉडल प्राप्त होगा जो आने वाली पीढ़ियों को अधिक बुद्धिमान, अधिक संवेदनशील और अधिक मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही इस महान योजना का वास्तविक महत्व,उद्देश्य और भविष्य है।

बाल कहानी : स्कूल का पहला दिन

टीकेश्वर सिन्हा गब्दीवाला
बालोद,छत्तीसगढ़

सुबह हुई। गौरैयाँ चह-चहाने लगीं। कौए का काँव-काँव सुन विनिता किचन से निकली। बेडरूम को झाँका। वैभव अब तक सोया ही था। बड़ी अचरज हुई। बिस्तर के करीब जाकर बोली- वैभव ! बेटा उठ ना। देखो तो, कितना टाइम हो गया है। आज स्कूल का पहला दिन है। स्कूल जाना है तुम्हें।

मम्मी का स्पर्श पाते ही वैभव ने आँखें खोली। अँगड़ाई लेते हुए ओढ़े हुए चादर हटाया। बोला-क्यों उठाया मम्मी आपने मुझे। सोने दो ना। नहीं जाऊँगा मम्मी आज स्कूल। पहला दिन है। कुछ नहीं होगा वहाँ आज। ठीक से बच्चे तक नहीं आएँगे;और न ही टीचर्स। मैं नहीं जाऊँगा।

न.. न...! स्कूल तो जाना ही है तुम्हें। कोई बहानेबाजी नहीं। पहले दिन तो स्कूल जाना चाहिए बेटा। उठो। विनिता ने वैभव को आगे कुछ और बोलने ही नहीं दिया। अब क्या करता बेचारा वैभव। उठा। तैयार हुआ। स्कूल के लिए निकल पड़ा।

वैभव इस साल कक्षा आठवी उत्तीर्ण हुआ था। एवरेज लेवल का छात्र था वह। नवमी में उसका एडमिशन हो चुका था। हाई स्कूल शब्द का भय थोड़ा उसके मन में तो था,पर खुश भी था कि अब उसे हाईस्कूल में पढ़ना है,और फिर दो बरस बाद हायर सेकेण्डरी। मन बड़ा प्रफुल्लित था उसका कि नये-नये दोस्त मिलेंगे। नये-नये टीचर्स से पढ़ने को मिलेगा। एक अच्छा नया माहौल मिलेगा। इस तरह वैभव के मन में तरह-तरह की बातें चल रही थी। उसे रास्ते चलने का पता ही नहीं चला, वह स्कूल पहुँच गया।

आज वैभव को एक नया स्कूल मिला। सहपाठियों से मुलाकात हुई। एक श्वेता नाम की लड़की ने वैभव को देख लिया। करीब आई। बोली- वैभव ! तुम भी यहीं पढ़ोगे ? वैभव ने मुँड़कर देखा- हाँ। यहीं पढ़ूँगा। तीन तारीख को आया था मैं एडमिशन के लिए अपने पापा के साथ।

श्वेता- अच्छा, वैभव तुम फर्स्ट डिवीजन पास हुए हो न ?

वैभव- हाँ,बयासी पर्सेंट है मेरा तो।

श्वेता- तुम्हें मैथ्स में कित्ता मार्क्स मिला है भाई ? मेरा तो बहुत कम आया है। केवल बैसठ ही।

वैभव- ओह ! मेरा तो ठीक ही है बहन। मेरा हाइएस्ट मार्क्स है इंग्लिश में। नाइन्टी वन है।

तभी वैभव व श्वेता को कुणाल ने पीछे से पहचान लिया। आवाज लगाई- श्वेता ! ऐ श्वेता...!

श्वेता इधर-उधर देखने लगी। कुणाल पास आया। बोला- मैं इधर हूँ, पिलर के पास।

श्वेता ने भी देख लिया कुणाल को। हँसी आ गई- अरे कुणाल तुम ! सब बढ़िया भाई ? फिर वैभव ने कुणाल से हाथ मिलाया- तू कितने समय आया। सायकल से आये हो ?

कुणाल- हाँ। और तुम ?

वैभव- पैदल। ये तो है मेरा घर। नजदीक में ही।

कुणाल- अच्छा लगा भाई तुम दोनों से मिलकर। मुझे न पिछले साल की मध्याह्न भोजन वाली घटना याद आ रही है। कुछ याद आया तुम्हें ?

वैभव झट से समझ गया-हा... हा....! हाँ यार। खूब मजा आया था। मैं नहीं भूल सकता भाई उस दिन को।

फिर कुणाल ने वैभव और श्वेता को अपने साथ आये लड़कों से परिचय कराया- ये है मनोरम; और ये नीतेश। सभी एक-दूसरे से मिले। सबको बड़ी खुशी हुई।

आज स्कूल की रौनकता तो देखते ही बनती। परिसर भर हरे-भरे पेड़-पौधे थे। रंग-बिरंगे मनमोहक फूल खिले थे। तभी दो लड़कियों के साथ प्रिया आई। श्वेता को गुड़हल का फूल देते हुए बोली- बहन ! वेलकम ! मैं प्रिया। दसवीं क्लास से हूँ।

श्वेता थोड़ी सी सकुचाई- थैंक यू दीदी। मैं श्वेता हूँ। नाइनन्थ में एडमिशन ली है।

प्रिया- मैं तो देख कर समझ गयी कि नई हो। चलो न बहन दसवीं क्लास;और लड़कियों से तुम्हें मिलाती हूँ। फिर सबके-सब एक-दूसरे से मिले। वैभव भी गया। उसे यह सब बहुत ही बढ़िया लग रहा था;यहाँ तक कि स्कूल का शोरगुल भी।

फिर सभी घूमने लगे। गैलरी भर महापुरुषों व शिक्षाविदों की तस्वीरें लगी थीं। दीवारों पर सुविचार लिखे हुए थे। वहीं पर शिखा मिल गयी। सभी एक-दूसरे को देख चहक उठे। उसने सबको देश के पूर्व राष्ट्पति व महान शिक्षाविद् डॉ.अब्दुल कलाम जी की पंक्तियाँ दिखाई-सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उक्त पंक्ति वैभव की जेहन को छू गयी। उसने तुरंत नोट कर ली।

प्रार्थना स्थल पर ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती व माँ भारती की प्रतिमा थी;और राष्ट्रध्वज स्तम्भ के बगल में राष्ट्रपिता बापू विराजमान थे।

प्रार्थना की घंटी लगी। बच्चे कतारबद्ध खड़े हुए। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना हुई। राष्ट्रगान हुआ। तीन बच्चों द्वारा सुविचार प्रस्तुत किये गये। फिर प्राचार्य ने समस्त शिक्षक व बच्चों को नव शिक्षासत्र की हार्दिक शुभकामनाएँ दी।

तत्पश्चात सभी शिक्षक एवं बच्चे सभाकक्ष में एकत्रित हुए। फिर प्राचार्य ने सभी नवप्रवेशी बच्चों के तिलक लगाया। मुँह मीठा किया। बच्चे बड़े खुश थे। पालकों की ओर से चॉकलेट बाँटी गयी। शिक्षकों ने उन पर पुष्प-पंखुरियाँ बरसाया। केवल वैभव को ही नहीं,बल्कि अन्य सभी नवप्रवेशी बच्चों को आज एक नई पहल देखने को मिल रही थी। सबके लिए एक नया अनुभव था। एक नयेपन का एहसास था। इन सबके साथ,जयकारे गूँजते रहे। तालियाँ भी बजती रही।

तदुपरांत मंच संचालन की बागडोर सम्भाले शिक्षक यदु जी ने कहा-आप सभी प्रायमरी व मीडिल स्तर से आये हुए हैं। बच्चो ! अब आप सब हाईस्कूल के विद्यार्थी हो गये। अब आप लोगों का शैक्षणिक स्तर बहुत बदल जाएगा। ऊँचे शैक्षणिक स्तर के लिए कठिन परिश्रम,लगन व समर्पण की जरूरत होती है। हम समस्त शिक्षक व अभिभावकगण आशान्वित हैं कि आप सभी सफल व होनहार विद्यार्थी के रूप में उभरेंगे। इस दरम्यान सभाकक्ष बिल्कुल शांत था। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे।

फिर शिक्षक ठाकुर जी बोले- बच्चो ! आप सभी समय का ध्यान रखेंगे। समय पर स्कूल आना होगा। समय पर ही छुट्टी होगी। स्कूल से सीधा घर जाना होगा। बच्चो,समय बड़ा मूल्यवान है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए अगर आप सभी समय के अनुसार चलेंगे, तो सफलता आप सबकी मुट्ठी में होगी।

इसी तरह सभी शिक्षकों ने विद्यार्थी हित की बातें कही। पालकों ने भी विद्यार्थी-जीवन पर प्रकाश डाला।

अंत में प्राचार्य ने अपनी संदेशपूर्ण बातें रखी- बच्चो ! हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल की पढ़ाई मानवीय जीवन की राहें प्रशस्त करती है। विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन की सीख मिलती है। मतलब,डिस्पिलीन मेक्स अ मेन परफेक्ट। बच्चो, सभी शिक्षक आप सबके हित में होंगे। यहाँ सभी विषयों के विशेषज्ञ हैं। सो,मेक दि मोस्ट ऑफ ऑल टीचर्स। बच्चो,आप सबकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। आप सबके माता-पिता की कामयाबी है। आज इस संस्था में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले दिन की सबको बधाई। मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।

चार बजे छुट्टी हुई। सबने घर की राह पकड़ी। हँसते-कुलकते बच्चे स्कूल मार्ग के रौनक थे।

वैभव के घर पहुँचते ही उसके पिता विनय कुमार बोले- क्यों वैभव,कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का पहला दिन ?

अच्छा रहा न ! सब ठीक-ठाक ? विनिता बोली।

अच्छा नहीं ! बहुत... बहुत... बहुत ही अच्छा ! आज मैं बहुत खुश हूँ। सोफे पर बैठ कर वैभव ने जूते निकाले;और मोजे को खींचते हुए बोला- मम्मी ! पापा ! मजा आ गया आज मेरा स्कूल का पहला दिन।

धुंधली लिखावट का धोखा

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

कमरे की वो सीलन भरी गंध अब भी ठीक वैसी ही थी जैसी अविनाश के जिंदा रहते हुआ करती थी। अलमारी का वह पुराना आधा खुला पल्ला जैसे किसी टूटे हुए जबड़े की तरह चिढ़ा रहा था। मैं उसकी बिखरी हुई दुनिया को समेटने के लिए फर्श पर बैठ गया तो पैरों के नीचे धूल की एक मोटी परत चरमरा उठी। अविनाश के अचानक चले जाने के बाद इस घर में सन्नाटा इतनी जोर से चिल्लाता था कि कान के पर्दे फटने लगते थे। अलमारी के सबसे ऊपरी खाने में हाथ डालते ही उंगलियों से एक पुरानी डायरी टकराई जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसी डायरी के भीतर से एक मोड़ा हुआ कागज का टुकड़ा नीचे गिरा जिस पर लिखा था कि तुम्हें यह तब मिलेगा जब मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। दिल की धड़कन ने एक पल के लिए जैसे हड़ताल कर दी और फेफड़ों में हवा जम गई। उस कागज पर स्याही के कुछ ऐसे धब्बे थे जो आंसुओं के गिरने से फैल गए थे। मुझे लगा कि कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन दबा रहा है और कमरे की खिड़की से आती धूप भी बर्फीली सुई की तरह चुभने लगी। मौत का यह कैसा क्रूर मजाक था कि जो इंसान जिंदगी भर अपनी हर बात को छुपाने का हुनर रखता था वह जाते-जाते एक ऐसा सुराग छोड़ गया जो मुझे जलती हुई भट्टी की तरफ खींच रहा था।

मैंने उस कागज को खोला तो अविनाश की वही कटी-फटी लिखावट सामने थी जो हमेशा किसी रहस्यमयी लिपि जैसी लगती थी। उसने लिखा था कि राहुल मुझे पता है कि तुम मुझे एक पत्थर दिल इंसान समझते रहे क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी उम्मीदों का जवाब नहीं दिया। पर सच तो यह है कि मैं तुम्हें उस दलदल से बचाना चाहता था जिसका सिरा सीधे इस अलमारी के पीछे छिपे लॉकर से जुड़ता है। तभी बाहर लॉबी में किसी के जूतों की आहट हुई और मेरा पूरा बदन पसीने से तर हो गया। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा पर वहां केवल सन्नाटा अपनी लंबी उंगलियां फैलाए खड़ा था। तभी मां ने रसोई से आवाज दी राहुल वहां क्या कर रहे हो इतनी देर से क्या तुम्हें कुछ मिला वहां।÷ मैंने अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए कहा नहीं मां यहां तो बस पुरानी रद्दी और धूल के सिवा कुछ भी नहीं है। मां ने एक लंबी ठंडी सांस ली और बोली उसकी चीजें जितनी जल्दी इस घर से बाहर चली जाएं उतना ही अच्छा है क्योंकि उसकी यादें अब इस घर को खाने लगी हैं। मां की इस बात में छुपा हुआ दर्द और नफरत का वह अजीब मिश्रण मुझे झकझोर गया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अविनाश ने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मां भी उसे माफ नहीं कर पा रही थी। मैं वापस उस अलमारी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उस भारी लकड़ी के ढांचे को पूरी ताकत से एक तरफ खिसकाया। दीवार के उस हिस्से पर सचमुच एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था जो बरसों से बंद रहने के कारण जंग खा चुका था।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

सुपरमैन की वापसी या सिस्टम की अधूरी जीत? दो लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल-क्या सप्लायर तक पहुंचेगी जांच?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार पर एक बार फिर आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग दो लाख रुपये मूल्य के 200 नशीले इंजेक्शनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या जांच केवल वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी या फिर इंजेक्शनों के बैच नंबर के आधार पर उस सप्लाई चेन तक भी पहुंचेगी, जहां से यह प्रतिबंधित दवाइयां युवाओं के हाथों तक पहुंच रही हैं? दिनांक 14 जून 2026 की रात गांधीनगर थाना क्षेत्र के सरना मैदान में आबकारी टीम ने संदिग्ध अवस्था में स्कूटी सवार एक व्यक्ति को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम वाहिद अंसारी निवासी लुंड्रा क्षेत्र बताया,जो वर्तमान में पटपरिया में किराये के मकान में रह रहा था। तलाशी के दौरान उसके बैग से 100 नग REXOGESIC इंजेक्शन और 100 नग AVIL इंजेक्शन बरामद किए गए। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

क्या सचमुच थम गया है नशे का कारोबार? सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने दावा किया है कि पिछले कई महीनों में लगातार कार्रवाई के कारण जिले में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री पर काफी हद तक रोक लगी है और कई विक्रेता जेल में हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ अलग तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के आदी युवाओं की मौजूदगी तथा समय-समय पर होने वाली बरामदगियां इस बात का संकेत देती हैं कि नेटवर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि कारोबार बंद हो चुका होता तो दो लाख रुपये मूल्य के इंजेक्शन एक व्यक्ति के पास इतनी व्यवस्थित पैकिंग में कैसे पहुंचते?

ऑपरेशन क्लीन की सफलता, लेकिन नेटवर्क अभी जिंदा? आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत यह कार्रवाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। सौ-सौ पुड़ियों में पैक इंजेक्शनों की बरामदगी इस बात की ओर संकेत करती है कि आरोपी खुद उपभोक्ता नहीं बल्कि वितरण श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे केवल 'कैरियर' या 'पेडलर' तक न रुकें,बल्कि उस आर्थिक नेटवर्क तक पहुंचें जहां से लाखों रुपये का कारोबार संचालित हो रहा है।

गिरफ्तारी से बड़ा सवालः माल आया कहां से?

जानकारों का कहना है कि किसी भी नशीली दवा के अवैध कारोबार का असली चेहरा तब सामने आता है जब जांच गिरफ्तार आरोपी से आगे बढ़कर सप्लायर, थोक विक्रेता, मेडिकल एजेंसी और वितरण नेटवर्क तक पहुंचती है। REXOGESIC और AVIL जैसे इंजेक्शनों पर बैच नंबर अंकित होते हैं। इन्हीं बैच नंबरों के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि दवा किस कंपनी ने बनाई, किस स्टॉकिस्ट को भेजी गई, किस मेडिकल एजेंसी ने खरीदी और अंततः वह किस दुकान या व्यक्ति तक पहुंची। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या आबकारी विभाग इस मामले में बैच नंबर की जांच कर सप्लाई चैन का खुलासा करेगा या फिर मामला केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित रह जाएगा?

पूर्व की कार्रवाइयों का क्या हुआ?

पिछले कुछ महीनों में संभागीय उड़नदस्ता टीम ने कई बड़े प्रकरण दर्ज किए हैं। लेकिन यह जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी कि उन मामलों में कितने सप्लायर, मेडिकल संचालक,एजेंट या वित्तीय सहयोगी गिरफ्तार हुए और कितनों को सजा मिली। यदि हर मामले में केवल निचले स्तर के विक्रेता ही पकड़े जाते हैं तो नशे का कारोबार कुछ समय बाद नए चेहरों के साथ फिर शुरू हो जाता है।

जनता जानना चाहती है...

- क्या REXOGESIC और AVIL इंजेक्शनों के बैच नंबर की जांच होगी?
- इंजेक्शन किस मेडिकल एजेंसी या सप्लायर से आए?
- क्या ड्रग विभाग को भी जांच में शामिल किया जाएगा?
- क्या इस नेटवर्क में और लोगों की गिरफ्तारी होगी?
- क्या पूर्व में पकड़े गए मामलों की तरह यह मामला भी केवल एक आरोपी तक सीमित रह जाएगा?

जनता की उम्मीद

वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी निश्चित रूप से आबकारी विभाग की एक महत्वपूर्ण सफलता है और कार्रवाई में शामिल टीम बधाई की पात्र है। लेकिन नशे के कारोबार पर स्थायी रोक तभी संभव है जब जांच इंजेक्शन के बैच नंबर से शुरू होकर सप्लाई चेन के आखिरी छोर तक पहुंचे । सरगुजा की जनता अब केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का खुलासा देखना चाहती है जो युवाओं के भविष्य को नशे की सुई के हवाले कर रहा है। सवाल अभी भी कायम है—क्या 'सुपरमैन' इस बार सप्लायर तक पहुंच पाएंगे, या फिर कार्रवाई केवल वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी तक ही सीमित रह जाएगी?

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार बेडसोर के लिए फ्लैप सर्जरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में पहली बार बेडसोर (प्रेशर अल्सर) के उपचार के लिए फ्लैप सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। जटिल मानी जाने वाली इस सर्जरी के सफल होने से क्षेत्र के मरीजों को अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले के भैयाथान निवासी 35 वर्षीय शोभनाथ पिछले 6 माह से पीठ पर बड़े बेडसोर की समस्या से पीड़ित थे। पैराप्लेजिया (शरीर के निचले हिस्से में लकवा) के कारण वे लंबे समय से बिस्तर पर थे। बेडसोर के कारण उन्हें प्रतिदिन ड्रेसिंग करानी पड़ती थी, जिससे मरीज और परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. आर्य के मार्गदर्शन और सलाह के बाद मरीज के स्थायी उपचार के लिए फ्लैप सर्जरी करने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार की सर्जरी आमतौर पर बड़े और उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में प्लास्टिक सर्जनों द्वारा की जाती है। 13 जून को सर्जरी विभाग की टीम ने मरीज का सफल ऑपरेशन किया। चिकित्सकों ने बताया कि बेडसोर अल्सर का आकार काफी बड़ा होने के कारण सर्जरी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति संतोषजनक है। बेहतर निगरानी और देखभाल के लिए उसे सर्जिकल आईसीयू में रखा गया है, जहां चिकित्सकों की टीम लगातार उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. मनोज भारती के नेतृत्व में डॉ. आनंद साहू एवं डॉ. अप्पू की भूमिका रही।

वहीं एनेस्थीसिया टीम में डॉ. रूपक कुमार और डॉ. शिवम शर्मा शामिल रहे। स्टाफ नर्स जैसिंटा ने भी ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार इस प्रकार की फ्लैप सर्जरी सफल होने को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

मुंडन संस्कार से लौट रही पिकअप ट्रैक्टर से टकराई,बुजुर्ग महिला की मौत,11 घायल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

मुंडन संस्कार कार्यक्रम से लौट रहे ग्रामीणों से भरी एक पिकअप रविवार रात अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग पर खड़े मिट्टी लोड ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए। घायलों में एक महिला का हाथ कंधे के पास से कटकर अलग हो गया, जिसे गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केंवरा निवासी हिमालय के पुत्र का रविवार को मुंडन संस्कार कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शामिल होने रिश्तेदारों और ग्रामीणों का दल दो पिकअप वाहनों में सवार होकर सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र स्थित रामगढ़ पहाड़ मंदिर गया था। वहां धार्मिक अनुष्ठान और मुंडन संस्कार संपन्न होने के बाद सभी शाम को अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब साढ़े 7 बजे पिकअप क्रमांक सीजी 15 एसी-3138 अंबिकापुर से लगभग 10 किलोमीटर पहले मेंड्राकला के पास सड़क पर खड़े मिट्टी लोड ट्रैक्टर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में सवार 12 लोग घायल हो गए। हादसे में प्रासदी राजवाड़े (पति स्वर्गीय कृपाल राजवाड़े) गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि उषा राजवाड़े का हाथ कंधे के पास से कटकर अलग हो गया।

पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, इलाज के दौरान मौत : घटना की सूचना मिलते ही मणिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह प्रासदी राजवाड़े की मौत हो गई। वहीं उषा राजवाड़े की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। मुंडन संस्कार की खुशी लेकर लौट रहे परिवार और ग्रामीणों पर हादसे ने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। महिला की मौत और कई लोगों के घायल होने से कार्यक्रम की खुशियां मातम में बदल गईं। जैसे ही हादसे की खबर केंवरा गांव पहुंची, पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतका का शव परिजनों को सौंप दिया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और सड़क किनारे खड़े वाहन को माना जा रहा है।

जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष : धान बुआई के दौरान ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या,8 आरोपी गिरफ्तार....

-संवाददाता-
बतौली,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलमा चिटकाही में वर्षों से चल रहा जमीन विवाद रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। विवादित भूमि पर धान बुआई को लेकर हुए टकराव में एक व्यक्ति की कथित रूप से ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक होंशराम पैंकरा और दूसरे पक्ष के भुवनेश्वर पैंकरा के बीच लंबे समय से भूमि स्वामित्व और कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण और न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद भी दोनों पक्ष उक्त भूमि पर अपना दावा करते रहे।

एक दिन पहले की गई थी धान बुआई : बताया जा रहा है कि मृतक होंशराम और उनकी पत्नी धनेश्वरी पैंकरा ने 13 जून को विवादित खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर धान की बुआई की थी। इसकी जानकारी मिलने पर अगले दिन दूसरे पक्ष के लोग भी ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंच गए और धान बुआई का कार्य शुरू कर दिया। इसी दौरान

दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गया।

ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप : प्रार्थिया धनेश्वरी पैंकरा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट की। आरोप है कि सभी आरोपी एकमत होकर मृतक होंशराम को खेत की मेड़ से नीचे धकेल दिए और इसके बाद ट्रैक्टर चालक उमेश ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक होंशराम बचने का प्रयास करते हुए ट्रैक्टर के बंपर से लटक गए, लेकिन गिरने के बाद ट्रैक्टर दोबारा उनके ऊपर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

राजस्व विवाद ने ली जान : स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस भूमि को लेकर विवाद हुआ, वह कई वर्षों से न्यायालय और राजस्व विभाग में विचाराधीन रही है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक स्तर पर समय रहते स्थायी समाधान नहीं निकल पाने के कारण अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी रहती है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि भूमि विवादों के संवेदनशील मामलों में प्रशासन द्वारा निगरानी और समयबद्ध समाधान कितना प्रभावी है।

8 आरोपी गिरफ्तार : पुलिस विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है–

- भुवनेश्वर पैंकरा (80 वर्ष)
- बजरंग लाल पैंकरा (60 वर्ष)
- रघुनंदन पैंकरा (52 वर्ष)
- मनोज कंवर (35 वर्ष)
- उमेश पैंकरा (23 वर्ष)
- बोधन पैंकरा (37 वर्ष)
- कमलेश्वरी पैंकरा (60 वर्ष)
- प्यारी पैंकरा (50 वर्ष)

सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई : डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में थाना बतौली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घटना के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर, लाठी-डंडे सहित अन्य साक्ष्य भी जब्त किए हैं। यह घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते भूमि विवादों की गंभीर तस्वीर भी सामने लाती है। सवाल यह है कि यदि वर्षों से चल रहे विवादित भूखंडों का समय रहते समाधान हो जाए तो क्या ऐसी जानलेवा घटनाओं को रोका जा सकता है? सरगुजा में हुई यह घटना बताती है कि खेत की मेड़ पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में एक परिवार का सहारा छीन सकता है। अब सभी की निगाहें न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस विवेचना पर टिकी हैं कि दोषियों को कितनी जल्दी और कितनी कठोर सजा मिलती है।

झाड़फूंक के बहाने घर में घुसा ढोंगी बाबा,नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

सरगुजा में अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा आया सामने,प्रयागराज का कथित बाबा गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास और झाड़फूंक के नाम पर महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक कथित ढोंगी बाबा की करतूत सामने आई है। आरोपी ने खुद को प्रयागराज से आया बाबा बताकर पहले परिवार का विश्वास जीता और फिर युवती को नौकरी व अच्छे रिश्ते का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। पुलिस के अनुसार आरोपी अमित कुमार गोस्वामी कॉलोनी में घूम-घूमकर लोगों की समस्याएं बताने और झाड़फूंक से समाधान करने का दावा कर रहा था। वह लोगों से पैसे और मोबाइल भी मांग रहा था। इसी दौरान वह पीड़िता के घर पहुंचा, जहां परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आरोपी ने युवती को यह कहकर अपने प्रभाव में लिया कि झाड़फूंक कराने से उसकी नौकरी लग जाएगी और अच्छा रिश्ता आएगा। आरोप है कि झाड़फूंक की प्रक्रिया के दौरान

आरोपी ने पीड़िता की मां को हनुमान मंदिर भेज दिया और बहन को कमरे से बाहर रहने के लिए कहा। घर के अन्य सदस्यों को अलग करने के बाद उसने युवती को अपने प्रभाव में लेकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने गांधीनगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता द्वारा बताए गए हुलिए और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित कुमार गोस्वामी (29 वर्ष) निवासी ग्राम सेमरा, थाना घुरपुर, जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक भारतीय मार्कण्डे, सहायक उपनिरीक्षक ललन गुप्ता सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आज भी समाज का एक वर्ग कथित चमत्कार, झाड़फूंक और ढोंगी बाबाओं के जाल में कैसे फंस जाता है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे व्यक्तियों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सरगुजा पुलिस का कहना है कि अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नीट-यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को होगी आयोजित जिले में 13 परीक्षा केंद्रों में 5212 परीक्षार्थी होंगे शामिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 परीक्षा का आयोजन आगामी 21 जून को जिले में 13 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा, जिसमें 5212 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल के साथ पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, बैठने की व्यवस्था, शौचालयों की साफ-सफाई तथा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्र पर निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने तथा यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

धर्म विशेष की प्रार्थना अनिवार्य करने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग,कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी स्कूलों में दैनिक प्रार्थना गतिविधियों को अनिवार्य किए जाने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग उठने लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने सरगुजा कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जारी दैनिक प्रार्थना संबंधी नियम एक धर्म

विशेष की धार्मिक आस्थाओं पर आधारित प्रतीत होते हैं,जो देश की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं हैं। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रशीद अहमद अंसारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में इस विषय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। रशीद अहमद अंसारी ने कहा कि वर्तमान समय में पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने के बजाय स्कूलों को साम्प्रदायिक राजनीति का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से आदेश वापस लेने अथवा उसमें संशोधन करने की मांग की। अंबिकापुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर शिक्षा नीतियों का निर्माण किया तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक हस्तक्षेप बढ़ा रही हैं,जो शिक्षा के मूल उद्देश्यों के विपरीत है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मो. इस्लाम, राजू बाबरा, पापिन्दर सिंह विखु, लुकस एक्का, अजय अरुण मिंज, जेनेबिब कुजूर, रूबी जैन, शिफ्तीन रजा, शकीला सिद्दीकी, विजय बेक, अली सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

CMYK

जल जीवन मिशन या 'जल इंतजार मिशन'?

दो साल से अधूरी पानी टंकी बनी ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए खतरा

करोड़ों की टंकी, लेकिन पानी नहीं,बांस-बल्ली अब भी लटकी, विभाग मौन

-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन कोरिया जिले के ग्राम पंचायत गेजी में यह योजना फिलहाल ग्रामीणों के लिए सुविधा से ज्यादा विडंबना का प्रतीक बनती जा रही है, करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित पानी टंकी आज भी अधूरी पड़ी है और ग्रामीणों की प्यास बुझाने के बजाय सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग दो वर्ष पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य आज तक पूरी तरह पूरा नहीं हो सका है, हालात यह हैं कि जिस टंकी को गांव के लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराना था, वह आज एक विशालकाय 'शोपीस' बनकर खड़ी है, ऊपर से विभागीय दावे विकास की गंगा बहाने के हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि टंकी के निर्माण में लगाई गई बांस-बल्ली और सेंटरिंग तक नहीं हटाई गई है।

दो साल बाद भी लटकी है सेंटरिंग, क्या यही है निर्माण गुणवत्ता?

ग्रामीण बताते हैं कि निर्माण कार्य के दौरान टंकी की ढलाई के लिए लगाए गए बांस-बल्ली आज तक नहीं हटाए गए हैं, दो वर्षों से धूप, बारिश और मौसम की मार झेल रहे ये बांस अब सड़ने लगे हैं और कई जगह टूटकर नीचे लटक रहे हैं, सवाल यह है कि यदि निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और भुगतान भी हो गया था तो फिर सेंटरिंग क्यों नहीं हटाई गई? क्या ठेकेदार भूल गया? क्या विभागीय अधिकारियों ने कभी निरीक्षण नहीं किया? या फिर फाइलों में टंकी पूरी बन गई और जमीन पर अधूरी छोड़ दी गई? ग्रामीणों का कहना है कि बांस-बल्ली किसी भी समय टूटकर गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है।

स्कूल के बच्चों पर मंडरा रहा खतरा

मामला और गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि पानी टंकी के ठीक समीप स्कूल स्थित है,स्कूल खुलने वाला है और प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे इसी रास्ते से आना-जाना करेंगे,यदि सड़ी हुई बांस-बल्ली अचानक टूटकर गिर जाए या कोई हिस्सा नीचे आ जाए तो उसकी चपेट में मासूम बच्चे आ सकते हैं, ग्रामीणों का कहना है कि विभाग शायद किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है,क्योंकि शिकायतों के बावजूद आज तक न तो सेंटरिंग हटाई गई और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए,ऐसा लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी यह मानकर बैठे हैं कि जब तक कोई हादसा नहीं होगा,तब तक कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

सीढ़ियां भी अधूरी,फिर कैसे होगा रखरखाव?

टंकी के ऊपर पहुंचने के लिए बनाई जाने वाली सीढ़ियां भी आज तक अधूरी हैं,आश्चर्य की बात यह है कि ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कार्य को पूर्ण दिखाकर राशि का आहरण भी कर लिया गया,यदि यह बात सही है तो सवाल उठता है कि आखिर अधूरी सीढ़ियों वाली टंकी को पूर्ण कैसे घोषित कर दिया गया? क्या गुणवत्ता परीक्षण हुआ था? क्या किसी अधिकारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था? क्या केवल कागजों में ही निर्माण पूरा माना गया? यदि सीढ़ियां अधूरी हैं तो भविष्य में टंकी के रखरखाव और मरम्मत का कार्य कैसे होगा?

टंकी के नीचे गड्ढे, सुरक्षा भगवान भरोसे-केवल टंकी ही नहीं, उसके आसपास का क्षेत्र भी उपेक्षा की कहानी बयां करता है, ग्रामीणों के अनुसार टंकी के नीचे समतलीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और खतरनाक हो सकती है, यानी ऊपर से सड़ी हुई सेंटरिंग और नीचे गहरे गड्ढे–बीच में आम ग्रामीण, शायद यही है 'विकास मॉडल' का नया संस्करण।

जल जीवन मिशन या कागजी जीवन मिशन?- देशभर में जल जीवन मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में गिना जाता है, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं, लेकिन गेजी की यह टंकी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है क्या योजनाएं वास्तव में जनता के लिए बन रही हैं या केवल आंकड़ों के लिए? क्योंकि यदि दो साल बाद भी टंकी चालू नहीं हो पाई, निर्माण अधूरा है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा, तो फिर योजना की सफलता का दावा किस आधार पर किया जा रहा है?

शिकायतें हुईं,लेकिन कार्रवाई नहीं...

ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, अधिकारियों को अवगत कराया गया, जनप्रतिनिधियों ने भी मामला उठाया, लेकिन परिणाम शून्य रहा, हर बार आश्वासन मिला, लेकिन सुधार नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि शिकायतों की फाइलें भी शायद उसी टंकी की तरह अधूरी अवस्था में कहीं पड़ी हुई हैं।

जवाब देने से बच रहे अधिकारी?

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी जानकारी देने में भी टालमटोल कर रहे हैं,जब निर्माण कार्य की स्थिति पूछी जाती है तो स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, जब गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो जांच की बात कही जाती है,जब समयसीमा पूछी जाती है तो कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जाती, ऐसे में लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

सबसे बड़ा सवाल-जिम्मेदार कौन?

यदि निर्माण अधूरा है तो जिम्मेदार कौन? यदि सेंटरिंग नहीं हटाई गई तो जिम्मेदार कौन? यदि बच्चों की सुरक्षा खतरे में है तो जिम्मेदार कौन? यदि भुगतान हो चुका है तो अधूरे काम का भुगतान किस आधार पर हुआ? और यदि भुगतान नहीं हुआ तो दो साल से काम रुका क्यों है? इन सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है।

ग्रामीणों की मांग...

- निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए।
- गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच हो।
- अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा कराया जाए।
- सड़ी हुई बांस-बल्ली और सेंटरिंग तुरंत हटाई जाए।
- स्कूल के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- दोषी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
- टंकी को जल्द से जल्द चालू कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

टंकी में पानी से ज्यादा सवाल भरे हैं...

गेजी की पानी टंकी आज विकास की कहानी कम और लापरवाही की मिसाल ज्यादा बन चुकी है,दो साल बाद भी अधूरी सीढ़ियां, सड़ती हुई सेंटरिंग,गड्ढों से घिरा परिसर,स्कूल के बच्चों पर खतरा,और विभागीय चुप्पी, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां 'जल जीवन मिशन' फिलहाल 'जल इंतजार मिशन' बन गया है,ग्रामीणों को अब सिर्फ पानी का इंतजार नहीं है,बल्कि उस दिन का इंतजार भी है जब जिम्मेदार अधिकारी फाइलों से निकलकर जमीन पर आएंगे और देखेंगे कि करोड़ों की लागत से बनी यह टंकी आखिर जनता की सेवा कर रही है या केवल सरकारी उपलब्धियों की सूची में एक और आंकड़ा बनकर खड़ी है।

मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की मजबूत नींव रखने का दावा,लेकिन 12 वर्षों की यात्रा पर सवाल भी कम नहीं

भाजपा ने गिनाईं केंद्र सरकार की उपलब्धियां,रोजगार,महंगाई और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर विपक्ष की नजर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 जून 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय संकल्प भवन, अम्बिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी अवधेश सिंह चंदेल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए इसे 'सेवा, सुशासन,विकास और गरीब कल्याण का स्वर्णिम काल' बताया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 से 2026 तक की यात्रा भारत के नव निर्माण की यात्रा रही है और विकसित भारत की परिकल्पना की मजबूत नींव इन 12 वर्षों में रखी जा चुकी है। प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. अम्बिकेश केशरी, महामंत्री विनोद हर्ष, महामंत्री अरुणा सिंह, जिला मीडिया प्रभारी रुपेश दुबे सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

'सबका साथ,सबका विकास' के दावे के साथ योजनाओं की लंबी सूची : अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। उन्होंने दावा किया कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है,जबकि कोरोना काल से लेकर वर्तमान तक 81 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं की सफलता के साथ-साथ जमीनी स्तर पर कई सवाल भी उठते रहे हैं। कई क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज की उपलब्धता तथा राशन वितरण व्यवस्था को लेकर शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं।

आवास, गैस और जल योजनाओं को बताया बड़ी उपलब्धि : चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देशभर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया गया तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई जगह पेयजल आपूर्ति की अनियमितता,अधूरे आवास और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों की शिकायतें बनी हुई हैं। विपक्ष लगातार यह सवाल उठाता रहा है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ और उनका स्थायी उपयोग अलग-अलग विषय हैं।

किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्यों का दावा,लेकिन कृषि संकट अब भी चर्चा में : प्रेसवार्ता में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा गया कि 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि अधोसंरचना और सस्ती ऋण सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया। लेकिन कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खेती की लागत, मौसम की अनिश्चितता, फसलों का मूल्य और बाजार व्यवस्था जैसे मुद्दे आज भी किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना और विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने बिना गारंटी ऋण और पीएम स्वनिधि योजना को भी गरीब एवं छोटे व्यवसायियों के लिए सहायक बताया। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि योजनाओं की सफलता का वास्तविक आकलन लाभार्थियों की आय में स्थायी वृद्धि और रोजगार सृजन के आधार पर होना चाहिए।

वैश्विक मंच पर बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा: भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। जी-20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका को उन्होंने इसकी मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को साकार करते हुए अनेक देशों की सहायता की और विश्व नेतृत्व की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं।

सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को नई पहचान : चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को भी नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कर्तव्य पथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी,नए संसद भवन,जनजातीय गौरव दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया है। हालांकि आलोचकों का मत है कि सांस्कृतिक परियोजनाओं के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी समान रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में मजबूती का दावा : प्रेसवार्ता में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हुई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिक सैन्य संसाधनों के विस्तार और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनाया गया। चंदेल ने कहा कि आज भारत ऐसा राष्ट्र है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन यदि कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है।

छत्तीसगढ़ को मिला विशेष लाभ : भाजपा-भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना,रेलवे विस्तार,सड़क निर्माण,हवाई सेवाओं और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास में केंद्र सरकार ने लगातार सहयोग दिया है। हालांकि प्रदेश में बेरोजगारी, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, शिक्षा और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे अभी भी राजनीतिक बहस के केंद्र में बने हुए हैं।

12 वर्षों की उपलब्धियां बनाम जनता की अपेक्षाएं : प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए विकसित भारत के निर्माण का दावा किया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल योजनाओं की संख्या या लाभार्थियों के आंकड़ों से नहीं,बल्कि रोजगार,महंगाई,कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिकों के जीवन स्तर में आए वास्तविक बदलाव से भी किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन 12 वर्षों बाद भी रोजगार,महंगाई, किसानों की आय, युवाओं के अवसर और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर बहस जारी है। ऐसे में आने वाले वर्षों में जनता इन दावों और वास्तविकताओं के बीच संतुलन को किस रूप में देखती है, यही देश की राजनीति और विकास की दिशा तय करेगा। प्रेसवार्ता के अंत में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने उपस्थित पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस अवसर पर रविशंकर जायसवाल,जतीन परमार सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नाम सुधार सूचना

मैं सोन प्रसाद पिता दिलेश्वर जाति घासी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम-बैजनाथपुर पोस्ट-बैजनाथपुर थाना-ओड़गी,तहसील-भैयाथान जिला- सूरजपुर (छ.ग.) ।

यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने नाबालिग पुत्री सनम (SANAM) से बदलकर सोनम सारथी (SONAM SARTHI) करवाना चाहता हूँ। जोकि मेरे पुत्री जन्म प्रमाण पत्र में वास्तविक नाम सोनम सारथी (SONAM SARTHI) है। मैं अपने पुत्री का नाम बदलकर,यदि कोई,गैर कानुनी काम करता हूँ तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। मेरे पत्नी तारा बाई को हमारे नाबालिग पुत्री के नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

शपथग्रहिता
सोन प्रसाद

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै रविन्द्र कुमार रजक (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री प्रेमनाथ रजक गाँव/शहर उदयपुर ,तहसील उदयपुर जिला -सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम अनुकल रजक (पुराना नाम) से बदल कर अनुकल्प रजक (नया नाम) रख लिया है।

पालक
रविन्द्र कुमार रजक
उदयपुर,तहसील उदयपुर
जिला -सरगुजा छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै ननकू राम (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री रामकिशून गाँव/शहर सिधमा,उप तहसील-बरियों ,तहसील राजपुर जिला -बलरामपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम कुमारी पुष्पांजली सिंह (पुराना नाम) से बदल कर पुष्पांजली सिंह (नया नाम) रख लिया है।

पालक
ननकू राम
सिधमा,उप तहसील-बरियों ,तहसील राजपुर जिला -बलरामपुर छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै सर्चना तरेनी तिर्की (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी सुभाष तिर्की गाँव/शहर गोधनपुर, अम्बिकापुर तहसील-अम्बिकापुर जिला -सरगुजा छ0ग0 ने अपना नाम सर्चना तरेनी तिर्की (पुराना नाम) से बदल कर सर्चता तरेनी तिर्की (नया नाम) रख लिया है।

आवेदक
सर्चना तरोनी तिर्की
गोधनपुर,अम्बिकापुर तहसील-अम्बिकापुर जिला -सरगुजा छ0ग0

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका प्रभुदयाल सोनी आ0 / पति स्व0 रामरतन सोनी जाति, निवासी नेहरू वार्ड सत्तीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 684 रकबा 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-25.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः-10.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका जानकी देवी साहू आ0 / पति ईश्वर प्रसाद साहू जाति, निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील ल अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-भट्ठापारा, शीट नम्बर-11 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4534/7 रकबा 14374.4 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-25.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-09.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 202504020700197 /अ-27/2024-25

फर्द बटवारा का अंतिम प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 202504020700197/अ-27/2024-25 पक्षकार रामू रजवार वगै. प्रति चेतन राम राजवाडे में ग्राम चिताबहार स्थित खसरा नंबर 70, 71, 72/1, 83/1, 92/1, 123/1, 368/2, 384/1 0.032, 0.008, 0.020, 0.069, 0.044, 0.061, 0.107, 0.503 हे. भूमि का फर्द बंटवारा सूची हल्का पटवारी से प्राप्त हुआ है, जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त फर्द बडवारा में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06/07/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 25/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा**

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगाव जिला सूरजपुर,छ.ग.

रा0प्र0क्र0 .....ब-121/2025-26

ईश्तहार

आम जनता ग्राम कटिन्दा को सूचित किया जाता है कि आवेदक सहादर राम आ0 बाबूलाल जाति घसिया निवासी ग्राम कटिन्दा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने बाबा स्व0 सुन्दर पिता चोमला का मृत्यु दिनांक 09/12/2010 को ग्राम कटिन्दा घर मे मृत्यु होना बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत मय आवेदन, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की प्रति सहित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म / मृत्यु) का रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) निगम 1969 के नियम 10 (13) के अन्तर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मृतक सुन्दर पिता चोमला का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18/06/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय मे अपना अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि बाद प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 04/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील — तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, भटगांव,जिला-सूरजपुर

न्यायालय लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर,छ.ग.

रा0प्र0क्र0 .....ब-121/2025-26

ईश्तहार

ग्राम पम्पापुर के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका शिवचरन साहू आ0/पति स्व0 रामधन साहू जाति तेली निवासी ग्राम पम्पापुर लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर,छ0ग0 द्वारा आवेदक/आवेदिका अपने भाई स्व0 रामकरण साहू का विलम्ब मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन कराने बावत अनुलब्धता प्रमाण पत्र, मय अन्य सहायक दस्तावेज के साथ न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया है मृत्यु दिनांक 24/12/2001

मृत्यू प्रमाण पत्र पंजीयन कराने बावत् अनुलब्धता के साथ न्यायलय में आवेदन पत्र पेश किया गया अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वम । अथवा किसी विविध प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 25/06/2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित कर दावा/आपत्ति पेश कर सकतें है । उसके पश्चात दावा आपत्ति में कोई विचार नही किया जायेगा ।

आज दिनांक 11/6/2026 को न्यायलीन पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया ।

सील — नायब तहसीलदार देवनगर जिला-सूरजपुर,छ0ग0

CMYK

कन्या विवाह योजना में 'मंगलसूत्र कांड' का आरोप 13 साल बाद खुला नियम, जानकारी क्यों रही गायब?

विभाग का जवाब आया की सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ

विवाद बढ़ता देख महिला एवं बाल विकास विभाग मैदान में उतरा, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति विवाह 50 हजार रुपये की सहायता निर्धारित है, इसमें 35 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में,8 हजार रुपये आयोजन एवं परिवहन पर,7 हजार रुपये उपहार सामग्री पर खर्च किए जाते हैं,विभाग ने विस्तार से बताया कि दुल्हनों को साड़ी,चूड़ी,बिछिया,सिंदूर,श्रृंगार पेटी,मंगलसूत्र और अन्य सामग्री दी गई थी, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2013 से चांदी के मंगलसूत्र की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है, अर्थात योजना में चांदी का मंगलसूत्र देना आवश्यक नहीं है, सरकारी भाषा में कहें तो जो दिया गया, नियम के अनुसार दिया गया।

लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है...

अगर कोई पाठक केवल प्रेस विज्ञप्ति का पहला हिस्सा पढ़े तो उसे लगेगा कि पूरा विवाद फर्जी था,लेकिन जैसे ही वह अंतिम पैराग्राफ तक पहुंचेगा, कहानी अचानक पलट जाती है,विभाग स्वयं स्वीकार करता है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई सामग्री में कुछ वस्तुएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं, यानी शिकायतों की जांच हुई, कमियां मिलीं,और इसके बाद आपूर्तिकर्ता के भुगतान से प्रति जोड़ा 1000 रुपये की कटौती कर दी गई, कुल 36 हजार रुपये हितग्राहियों के खातों में जमा कराए गए, यहीं पर सवाल पैदा होता है,अगर सब कुछ बिल्कुल सही था तो कटौती क्यों हुई? और अगर कटौती हुई तो शिकायतें पूरी तरह गलत कैसे हो गईं? यही वह प्रश्न है जिसने पूरे मामले को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

सत्ता बदली,विपक्ष बदला,लेकिन जानकारी नहीं बदली

यह मामला इसलिए भी रोचक हो जाता है क्योंकि पिछले 13 वर्षों में प्रदेश की राजनीति कई बार करवट बदल चुकी है,2013 से 2018 तक एक सरकार रही, 2018 से 2023 तक दूसरी सरकार रही, फिर सत्ता दोबारा बदली, लेकिन किसी भी दौर में यह जानकारी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनी, आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है,लेकिन जनता पूछ रही है कि जब विपक्ष पांच साल तक खुद सरकार में था, तब उसे भी यह नियम क्यों याद नहीं आया? और सत्ता पक्ष से भी सवाल है कि यदि यह नियम इतना स्पष्ट था तो वर्षों तक इसकी जानकारी लाभार्थियों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई?

असल विवाद मंगलसूत्र का नहीं,सूचना का है...

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी विफलता यदि कहीं दिखाई देती है तो वह सूचना प्रबंधन की है, सरकारी योजनाओं में अक्सर यही होता है, आदेश राजधानी में निकलता है,फाइल जिलों तक पहुंचती है,बैठकों में पढ़ा जाता है, निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज होता है,लेकिन जिस व्यक्ति के लिए योजना बनाई गई है, उसे इसकी जानकारी नहीं मिलती,यहां भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, यदि विवाह से पहले लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाता कि योजना में चांदी का मंगलसूत्र शामिल नहीं है,तो क्या यह विवाद पैदा होता? संभवतः नहीं,यदि आवेदन पत्र, सूचना पुस्तिका,विवाह पूर्व बैठक और कार्यक्रम स्थल पर यह बात लिखी होती,तो क्या सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते? शायद नहीं।

सरकारी खंडन या सरकारी स्वीकारोक्ति?

राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि किसी आरोप का जवाब देते-देते जवाब देने वाला ही नया तथ्य उजागर कर देता है, यह मामला भी कुछ वैसा ही दिखाई देता है,विभाग यह साबित करना चाहता था कि सामूहिक विवाह में कोई अनियमितता नहीं हुई,लेकिन उसी सफाई में यह भी बताया गया कि सामग्री गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी थी,अब जनता असमंजस में है,एक तरफ कहा जा रहा है कि आरोप गलत हैं,दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सामग्री में कमी थी,ऐसे में आम आदमी यही पूछ रहा है साहब, अगर माल बढ़िया था तो पैसा क्यों काटा गया? और अगर पैसा काटा गया तो शिकायत करने वाले झूठे कैसे हो गए?

मंगलसूत्र,माला और सवालों का महाभारत...सरकारी खंडन आया,लेकिन जवाब ज्यादा मिले या नए प्रश्न?

चार महीने पुरानी शादी,एक वायरल वीडियो और विभाग का सफाईनामा...आखिर सच क्या है?

मंगलसूत्र से बड़ा सवाल...13 साल तक फाइलों में क्यों बंद रहा सच?

मंगलसूत्र विवाद में नया मोड़...खंडन ने खोले 13 साल पुराने राज

गरीब बेटियों के गले में सवालों की माला, फाइलों में बंद रहा नियम

मंगलसूत्र पर मचा बवाल,लेकिन असली विवाद निकला 'जानकारी का अकाल'

2013 में बदला नियम,2026 में मिली जानकारी! आखिर जिम्मेदार कौन?

खंडन आया,मगर सवाल रह गया,13 साल तक किसने छिपाए रखे नियम?

नियम बदला,सरकारें बदलीं,लेकिन जनता को खबर नहीं मिली!

सवालों के घेरे में व्यवस्था,चांदी का मंगलसूत्र नहीं था तो बताया क्यों नहीं गया?

184 शादियां,एक विवाद और 13 साल पुरानी चुप्पी

संचालक
संचालनालय महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर छत्तीसगढ़

सरकारी खंडन

कन्या विवाह योजना में 'मंगलसूत्र कांड' का आरोप
नवविवाहिताओं के गले में सम्मान या सवालों की माला?
179 जोड़ों के सामूहिक विवाह के चार महीने बाद उठा विवाद
कांग्रेस ने कलेक्टर से मांगी उच्चस्तरीय जांच

-संवाददाता-
एमसीबी,15 जून 2026
(घटती-घटना)।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत फरवरी में संपन्न हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का मामला अब केवल एक मंगलसूत्र तक सीमित नहीं रह गया है, यह मामला सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता, निगरानी, जवाबदेही और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का ऐसा संगम बन चुका है, जिसमें हर पक्ष अपने-अपने सच की माला गूंथ रहा है, कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नवविवाहिताएं अपने गले में पड़े मंगलसूत्र दिखाते हुए सवाल पूछ रही थीं,विपक्ष सक्रिय हो गया,जांच की मांग उठने लगी, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई और मामला अखबारों की सुर्खियों तक पहुंच गया, विपक्ष इसे गरीब बेटियों के सम्मान का अपमान बता रहा था, स्थानीय स्तर पर जांच की मांग उठ रही थी,और अब महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए खंडन कर दिया है, लेकिन सरकारी खंडन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि विवाद खत्म होने के बजाय एक नए मोड़ पर पहुंच गया है।

पहले समझिए पूरा मामला...

10 फरवरी 2026 को खड़गवां के चनवारीडांड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कार्यक्रम में 184 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, शासन की योजना के अनुसार नवदंपतियों को विभिन्न प्रकार की उपहार सामग्री प्रदान की गई,सब कुछ सामान्य चल रहा था, फिर चार महीने बाद अचानक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होने लगे, वीडियो में दावा किया गया कि नवविवाहिताओं को जो मंगलसूत्र दिए गए थे,वे बेहद निम्न गुणवत्ता के हैं, कुछ लोगों ने तो इसे नकली तक बता दिया, मामला देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में पहुंच गया, विपक्ष ने इसे गरीब बेटियों के सम्मान से जोड़ दिया, स्थानीय नेताओं ने जांच की मांग कर दी, और देखते ही देखते एक साधारण मंगलसूत्र राजनीतिक परमाणु बम में बदल गया।

मंगलसूत्र नहीं,भरोसे की परीक्षा

भारतीय समाज में मंगलसूत्र केवल आभूषण नहीं होता,यह विवाह का प्रतीक माना जाता है,भावनाओं से जुड़ा होता है,गरीब परिवार की बेटी जब सरकारी योजना के तहत विवाह करती है तो उसके लिए दिया गया हर सामान सम्मान का प्रतीक होता है,ऐसे में यदि गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो मामला केवल धातु या डिजाइन का नहीं रह जाता,यह भरोसे का विषय बन जाता है,योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की मदद करना है,लेकिन यदि लाभार्थी ही संतुष्ट नहीं दिखें तो योजना की छवि प्रभावित होना स्वाभाविक है।

ठेकेदार मॉडल बनाम सम्मान मॉडल

पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू खरीद प्रक्रिया है सवाल यह है कि सामान खरीदा किस आधार पर गया? गुणवत्ता की जांच कब हुई? यदि जांच बाद में हुई तो वितरण से पहले क्यों नहीं? क्या सामग्री का परीक्षण हुआ था? क्या गुणवत्ता प्रमाणन मौजूद है? क्या खरीद समिति ने भौतिक सत्यापन किया था? ये वे प्रश्न हैं जिनका जवाब प्रेस विज्ञप्ति में नहीं मिलता, और यही कारण है कि विवाद समाप्त होने के बजाय और गहरा होता दिखाई देता है।

चार महीने तक सब शांत था,फिर अचानक बवाल क्यों?

यह भी दिलचस्प प्रश्न है, फरवरी में विवाह हुआ, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई भी बीत गया,फिर जून आते-आते मामला अचानक सुर्खियों में कैसे आ गया? क्या लाभार्थियों ने बाद में शिकायत की? क्या राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाया? क्या किसी ने वीडियो वायरल कर दिया? या फिर चुनावी मौसम की आहट ने इस मामले को नया जीवन दे दिया? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है।

सबसे बड़ा नुकसान किसका?

राजनीतिक दल अपना पक्ष रखेंगे,अधिकारी अपना बचाव करेंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा,सरकार जवाब देगी,लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस योजना की विश्वसनीयता का होता है,जिसे गरीब परिवारों के लिए बनाया गया है, जब लाभार्थी योजना से जुड़ी सामग्री को लेकर असंतोष जताते हैं तो भविष्य के लाभार्थियों का भरोसा भी प्रभावित होता है।

अब निगाहें प्रशासन पर...

विभाग का खंडन आ चुका है,लेकिन अब जनता को केवल खंडन नहीं, पारदर्शिता चाहिए,यदि जांच हुई थी तो रिपोर्ट सार्वजनिक हो,यदि गुणवत्ता में कमी मिली थी तो संबंधित आपूर्तिकर्ता पर क्या कार्रवाई हुई? यदि भुगतान काटा गया तो किन वस्तुओं में कमी पाई गई? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर ही विवाद को समाप्त कर सकता है।

माला अभी पूरी नहीं हुई...

सरकारी प्रेस विज्ञप्ति ने विवाद को दबाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे तथ्य भी सामने रख दिए हैं जिन्होंने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि सब कुछ नियमानुसार हुआ, दूसरी तरफ दस्तावेज खुद बता रहा है कि सामग्री मानक के अनुरूप नहीं थी और भुगतान में कटौती करनी पड़ी,यानी कहानी का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है,फिलहाल खड़गवां के सामूहिक विवाह कार्यक्रम से निकला यह विवाद यही संदेश दे रहा है कि गरीब बेटियों के सम्मान की माला में यदि एक भी कड़ी कमजोर होगी, तो सवालों की पूरी माला तैयार होने में देर नहीं लगेगी, और अभी ऐसा लगता है कि मंगलसूत्र का विवाद खत्म नहीं हुआ है, बस सरकारी खंडन और जनसवालों के बीच अगली कड़ी का इंतजार कर रहा है।

13 साल बाद जनता को पता चला कि चांदी का मंगलसूत्र अनिवार्य ही नहीं था! ... विभाग ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि 14 जनवरी 2013 को ही शासन ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में चांदी के मंगलसूत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी,यानी जिस मुद्दे पर आज पूरा विवाद खड़ा है,वह नियम तो तेरह साल पहले ही बदल चुका था,बस यहीं से असली सवाल पैदा होता है,अगर 2013 में नियम बदल गया था तो 2026 में जनता को इसकी जानकारी पहली बार क्यों मिल रही है? क्या यह जानकारी केवल सरकारी फाइलों,नोटशीटों और आदेश पुस्तिकाओं तक सीमित थी? क्या 13 वर्षों तक किसी ने यह जरूरी नहीं समझा कि लाभार्थियों को भी बताया जाए कि योजना में अब चांदी का मंगलसूत्र नहीं दिया जाता?

साल-सागौन की अवैध कटाई से जंगल बेहाल,जिम्मेदारों की कार्यशैली पर उठे सवाल

छिंगरा, कर्री, रजपुरी, भलुवार और अमहर के जंगलों में बेखौफ सक्रिय वन माफिया

-राजन पाण्डेय-
सोनहत/कोरिया,15 जून 2026
(घटती-घटना)।
सोनहत वन परिक्षेत्र के घने जंगल इन दिनों अवैध कटाई के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं,क्षेत्र के छिंगरा,कर्री,रजपुरी,भलुवार और अमहर सहित कई इलाकों में साल और सागौन जैसी बेशकीमती लकड़ियों की लगातार कटाई किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन माफिया जंगलों में बेखौफ होकर सक्रिय हैं, जबकि वन विभाग का मैदानी अमला प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है,ग्रामीणों का कहना है कि जिन जंगलों की रक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग पर है, वहीं आज सबसे अधिक असुरक्षित नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही कटाई से जंगलों का स्वरूप बदल रहा है और पर्यावरणीय संतुलन पर भी खतरा मंडराने लगा है।

जंगलों में नहीं दिख रही निगरानी

स्थानीय लोगों के अनुसार वन विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने के बजाय मुख्यालय तक सीमित दिखाई देते हैं, जंगलों में निगरानी और गश्त की कमी का फायदा उठाकर लकड़ी तस्कर खुलेआम पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि यदि नियमित गश्त और निगरानी होती तो इतनी बड़ी मात्रा में अवैध कटाई संभव नहीं होती। वन विभाग की निष्क्रियता के कारण तस्करों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

जब्त लकड़ियां खुले में सड़ रहीं,राजस्व को हो रहा नुकसान

वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल केवल अवैध कटाई तक सीमित नहीं हैं, क्षेत्र में पूर्व में जब्त की गई कीमती लकड़ियों के लंबे समय से खुले में पड़े रहने की भी शिकायतें सामने आई हैं, जानकारों का कहना है कि नियमानुसार जब्त लकड़ियों को समय पर काष्ठागार भेजा जाना चाहिए या नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर राजस्व अर्जित किया जाना चाहिए, लेकिन लंबे समय से लकड़ियों के खुले में पड़े रहने से उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और विभाग को संभावित राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दावानल के बाद अब अवैध कटाई पर भी सवाल

क्षेत्रवासियों का कहना है कि कुछ समय पहले जंगलों में लगी आग की घटनाओं के दौरान भी वन विभाग की सक्रियता सवालों के घेरे में रही थी, अब अवैध कटाई के लगातार सामने आ रहे मामलों ने विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर प्रश्नचिह्न लगा दिया है,लोगों का कहना है कि यदि जंगलों को आग से बचाने और अवैध कटाई रोकने दोनों मोर्चों पर विभाग प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा है,तो वन संरक्षण के दावों की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

देवगढ़ रेंज के घुघरा क्षेत्र में भी कटाई की शिकायत

सोनहत क्षेत्र के अलावा देवगढ़ रेंज के घुघरा इलाके में भी यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायतें सामने आई हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां भी वन माफिया सक्रिय हैं और बिना किसी डर के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने वन विभाग की गश्त, निगरानी व्यवस्था और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कार्रवाई की मांग तेज

क्षेत्रवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है,उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में क्षेत्र के जंगलों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है,अब लोगों की नजर वन विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हुई है कि वे जंगलों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाते हैं या फिर अवैध कटाई का यह सिलसिला यूं ही जारी रहता है।

फाइलों का लोकतंत्र और जिम्मेदारी का वनवास

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक विचित्र सिद्धांत है,जब कोई योजना सफल होती है तो उसका श्रेय ऊपर तक पहुंचता है,लेकिन जब कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी नीचे की सबसे कमजोर कड़ी पर छोड़ दी जाती है, सूरजपुर का यह मामला भी कहीं उसी परंपरा का नया अध्याय तो नहीं? यदि आदेश फर्जी था तो फाइल देखने वाले अधिकारी कौन थे? यदि आदेश संदिग्ध था तो उसे रोकने वाला कौन था? यदि आदेश गलत था तो उसे लागू करने वाले कौन थे? और यदि आदेश सही था तो उसे फर्जी घोषित करने का आधार क्या है? इन सवालों के जवाब बिना यह कहानी अधूरी रहेगी।

डिजिटल इंडिया बनाम मानवीय भूल

सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है,ई-ऑफिस की बात करती है, साइबर सुरक्षा की बात करती है,लेकिन जमीन पर अक्सर वही पुराना सवाल सामने आ जाता है–सिस्टम मजबूत है या सिर्फ उसका प्रचार? यदि एक कथित फर्जी आदेश पूरा प्रशासनिक ढांचा पार कर सकता है,तो फिर समस्या किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि उस तंत्र में भी है जो खुद को सुरक्षित और पारदर्शी बताता है।

असली जांच अभी बाकी है...

आज शिक्षिका कटघरे में है, कल शायद कोई और होगा,लेकिन यदि व्यवस्था के भीतर मौजूद कमियां उजागर नहीं हुईं तो ऐसे मामले बार-बार सामने आते रहेंगे, इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि किसे आरोपी बनाया गया,सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जांच की दिशा क्या है,क्या जांच केवल आरोपी खोज रही है? या फिर उस रास्ते को भी तलाश रही है जिससे कथित रूप से फर्जी आदेश सरकारी सिस्टम के भीतर प्रवेश कर गया?

अंतिम सवाल...

सूरजपुर का यह मामला केवल एक शिक्षिका,एक स्थानांतरण आदेश और एक एफआईआर की कहानी नहीं है,यह डिजिटल प्रशासन,विभागीय जवाबदेही और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा है,यदि आदेश फर्जी था तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए,लेकिन यदि सिस्टम ने भी आंखें बंद रखीं तो फिर सवाल केवल एक व्यक्ति पर नहीं,पूरी व्यवस्था पर उठेंगे,क्योंकि जनता अब यह जानना चाहती है फर्जी आदेश किसने बनाया,यह तो जांच बताएगी; लेकिन उसे पहचानने में पूरा सिस्टम क्यों नाकाम रहा,इसका जवाब कौन देगा?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,15 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल शासन,ई-ऑफिस और पेपरलेस प्रशासन का सपना जनता को दिखा रही है, दावा किया जा रहा है कि अब फाइलें गायब नहीं होंगी,आदेशों में हेरफेर नहीं होगा, डिजिटल हस्ताक्षर सुरक्षा की गारंटी होंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी,लेकिन सूरजपुर जिले से सामने आया एक मामला इन दावों के बीच ऐसा सवाल बनकर खड़ा हो गया है,जिसका जवाब केवल एक शिक्षिका के खिलाफ दर्ज एफआईआर से नहीं मिलेगा।

मामला एक कथित फर्जी स्थानांतरण आदेश का है, शिक्षा विभाग का दावा है कि एक शिक्षिका ने फर्जी आदेश प्रस्तुत कर स्थानांतरण का लाभ लिया, विभागीय जांच हुई, निलंबन हुआ,पुलिस में प्राथमिकी दर्ज हुई और मामला अब कानून के दरवाजे तक पहुंच गया,लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती,असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आदेश फर्जी था या नहीं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि

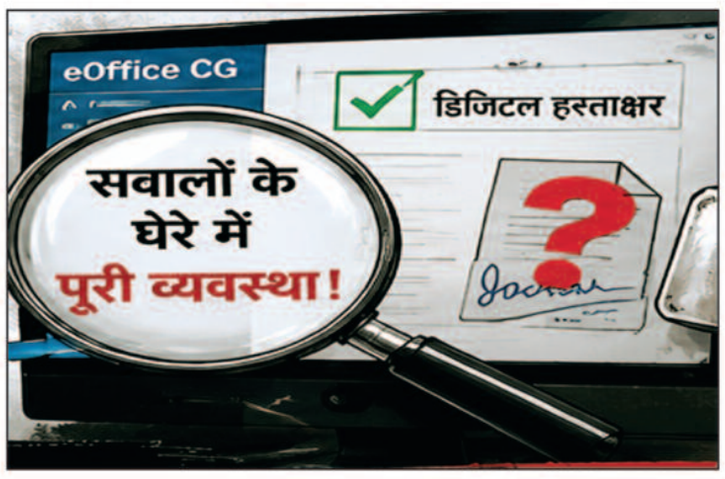

आदेश फर्जी था, तो फिर पूरा सिस्टम असली कैसे माना जाए?

फर्जी आदेश आया कहां से?

सरकारी कार्यालयों में कोई भी आदेश सीधे आसमान से नहीं टपकता, उसके पीछे प्रस्ताव बनता है, फाइल चलती है, अनुमोदन होता है, डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, फिर आदेश जारी होता है, अब यदि शिक्षा विभाग यह कह रहा है कि स्थानांतरण आदेश फर्जी था, तो पहला सवाल यही बनता है कि वह आदेश संबंधित शिक्षिका तक पहुंचा कैसे? क्या किसी ने व्हाट्सऐप पर भेज दिया? क्या किसी बाबू ने फाइल से निकालकर दे दिया? क्या किसी अधिकारी ने उसे वैध माना? या फिर डिजिटल युग में कोई ऐसा जादूगर पैदा हो गया जिसने शासन के सर्वर में घुसकर आदेश तैयार कर दिया? यदि आदेश फर्जी था तो उसकी उत्पत्ति का स्रोत पता लगाना सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी,लेकिन चर्चा यह है कि कार्रवाई का पूरा केंद्र सिर्फ शिक्षिका को बनाया गया।

शिक्षिका दोषी या सिस्टम का सुविधाजनक निशाना?

यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में फर्जी दस्तावेज तैयार किया है तो कानून अपना काम करेगा,लेकिन क्या केवल लाभ लेने वाला ही दोषी है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में नकली चेक लेकर पहुंचता है, बैंक यदि बिना जांच के भुगतान कर देता है तो क्या बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ठीक यही सवाल शिक्षा विभाग पर भी लागू होता है,यदि कथित फर्जी आदेश के आधार पर कार्यमुक्ति हुई,पदस्थापना हुई,वेतन प्रक्रिया चली और महीनों तक किसी को संदेह नहीं हुआ,तो फिर विभाग के सत्यापन तंत्र का क्या हुआ? क्या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने आदेश की जांच नहीं की? क्या विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने उसे सत्यापित नहीं किया? क्या कार्यालयों में बैठे अधिकारियों ने केवल मुहर लगाने का काम किया? यदि हां,तो फिर दोष केवल एक व्यक्ति का कैसे हो सकता है?

निलंबन की रफ्तार और जांच की चाल

इस मामले में निलंबन और एफआईआर की कार्रवाई तेजी से हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसी तेजी से यह भी जांच हुई कि आदेश को स्वीकार किसने किया? उस पर भरोसा किसने किया? उसके आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई किसने की? यदि जांच का दायरा केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहेगा तो यह न्याय नहीं, बल्कि सुविधाजनक प्रशासन कहलाएगा, क्योंकि व्यवस्था की सबसे पुरानी बीमारी यही है कि गलती सामूहिक होती है और कार्रवाई व्यक्तिगत।

शिक्षा विभाग और वायरल आदेशों की पुरानी कहानी

दिलचस्प बात यह है कि यह पहला अवसर नहीं है जब शिक्षा विभाग में आदेशों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हो, हाल ही में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर 12 जून 2026 के दो अलग-अलग आदेश सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, बाद में उनमें से एक को फर्जी बताया गया, पूरा प्रदेश असमंजस में रहा, शिक्षक समझ नहीं पाए कि कौन-सा आदेश मान्य है और कौन-सा नहीं,यह घटना बताती है कि विभागीय आदेशों की प्रमाणिकता को लेकर पहले से ही भ्रम मौजूद है,ऐसे में यदि कोई कर्मचारी किसी आदेश को वास्तविक मानकर कार्रवाई करता है, तो उसकी भूमिका और मंशा की निष्पक्ष जांच भी आवश्यक है।

क्या पुराने आदेशों की भी होगी जांच ?

यह मामला एक और बड़ा प्रश्न खड़ा करता है,यदि आज एक कथित फर्जी स्थानांतरण आदेश पकड़ा गया है,तो क्या पिछले वर्षों के आदेशों की भी समीक्षा होगी? क्या यह जांचा जाएगा कि कहीं पहले भी ऐसे आदेशों के आधार पर पदस्थापनाएं,स्थानांतरण या अन्य लाभ तो नहीं लिए गए? क्योंकि यदि एक मामला पकड़ा गया है तो यह मान लेना कि बाकी सब कुछ शत-प्रतिशत सही था,शायद जल्दबाजी होगी,व्यवस्था में यदि एक दरार दिखाई देती है तो जिम्मेदार जांच एजेंसियां पूरी दीवार की मजबूती भी जांचती हैं।

डिजिटल युग में एनालॉग लापरवाही

सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर ई-ऑफिस लागू कर रही है,डिजिटल हस्ताक्षर लागू किए जा रहे हैं,ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है,लेकिन सूरजपुर का यह मामला पूछ रहा है कि क्या तकनीक केवल दिखावे के लिए है? यदि एक कथित फर्जी आदेश पूरा प्रशासनिक रास्ता पार कर सकता है,तो फिर ई-ऑफिस का लाभ क्या हुआ? व्यंग्य यह है कि कागज के युग में कहा जाता था कि फाइल गायब हो गई, अब डिजिटल युग में कहा जा रहा है कि आदेश ही असली नहीं था,तकनीक बदल गई,लेकिन बहाने का स्वरूप केवल आधुनिक हो गया।

खड़गवां वन परिक्षेत्र में पौधारोपण से पहले उठे सवाल

ठेकेदारी व्यवस्था से पौधों के नष्ट होने का खतरा, स्थानीय व्यवस्था छोड़ने पर ग्रामीणों ने जताई चिंता

-संवाददाता-

खड़गवां (एमसीबी),15 जून 2026 (घटती-घटना)।

वन विभाग द्वारा आगामी पौधारोपण अभियान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही परिवहन व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं,वन परिक्षेत्र खड़गवां में नर्सरी से विभिन्न कम्पार्टमेंटों और रोपण स्थलों तक पौधों की ढुलाई के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों, पर्यावरण प्रेमियों और वन कार्यों से जुड़े जानकारों ने चिंता व्यक्त की है, उनका कहना है कि यदि पौधों की ढुलाई पूरी तरह ठेकेदारी व्यवस्था के भरोसे छोड़ दी गई तो पौधारोपण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और बड़ी संख्या में पौधों के नष्ट होने की आशंका बढ़ सकती है।

स्थानीय व्यवस्था से अब तक सुरक्षित पहुंचते थे पौधे

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्षों में वन विभाग के स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटे वाहनों और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से पौधों को सीधे रोपण स्थलों तक पहुंचाते रहे हैं,जंगलों के भीतर स्थित कठिन और दुर्गम स्थानों तक पौधों को सावधानीपूर्वक ले जाया जाता था,जिससे उनकी जड़ों और शाखाओं को नुकसान नहीं पहुंचता था,स्थानीय लोगों का मानना है कि क्षेत्र की परिस्थितियों को समझने वाले कर्मचारियों की निगरानी में पौधों की ढुलाई अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहती थी और पौधों के जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती थी।

बड़े वाहन सड़क तक पहुंचेंगे, फिर कौन ले जाएगा पौधे अंदर ?

जानकारों के अनुसार सबसे बड़ी चिंता यह है कि निविदा प्राप्त करने वाले ठेकेदार कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बड़े वाहनों का उपयोग करेंगे,लेकिन वन क्षेत्रों के कई रोपण स्थल ऐसे हैं जहां तक बड़े ट्रक या भारी वाहन नहीं पहुंच सकते, ऐसी स्थिति में पौधों को सड़क किनारे उतारकर बाद में छोटे साधनों या श्रमिकों के माध्यम से अंदर पहुंचाना पड़ेगा। इस दोहरी प्रक्रिया के दौरान पौधों के टूटने,जड़ों के क्षतिग्रस्त होने और धूप में लंबे समय तक पड़े रहने से उनके सूखने का खतरा बढ़ सकता है।

हर पौधा महत्वपूर्ण, करोड़ों की योजना पर पड़ सकता है असर

वन विभाग हर वर्ष लाखों रुपये खर्च कर पौधारोपण अभियान चलाता है,इन अभियानों का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं,बल्कि उन्हें जीवित रखना और भविष्य का हरित आवरण तैयार करना होता है,विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परिवहन के दौरान पौधों की उचित देखभाल नहीं हुई तो पौधारोपण की सफलता दर प्रभावित हो सकती है। इससे न केवल सरकारी धन का नुकसान होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाए रखने की मांग...

क्षेत्रवासियों और वन कार्यों से जुड़े लोगों ने मांग की है कि पौधों की ढुलाई की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही कराई जाए, उनका कहना है कि स्थानीय वाहन चालकों, श्रमिकों और वन कर्मचारियों की निगरानी में पौधों को सुरक्षित रूप से रोपण स्थलों तक पहुंचाया जा सकता है, ग्रामीणों का तर्क है कि स्थानीय लोगों को क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, रास्तों और मौसम की बेहतर जानकारी होती है, जिससे पौधों के नुकसान की संभावना कम रहती है।

अब विभाग के फैसले पर टिकी निगाहें...

पौधारोपण अभियान शुरू होने से पहले उठे इन सवालों ने वन विभाग के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि पौधे केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी हरे-भरे दिखने चाहिए, ऐसे में परिवहन व्यवस्था का निर्णय अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, अब सभी की निगाहें वन विभाग पर टिकी हैं कि वह स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की आशंकाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है या नहीं, यदि समय रहते उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई तो हरियाली बढ़ाने का सपना कहीं कागजों तक सीमित होकर न रह जाए।

केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी

मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां

जनता तक पहुंचा रही भाजपा : उज्ज्वल दीपक

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,15 जून 2026 (घटती-घटना)।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने मनेन्द्रगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों,जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन,आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, किसान,महिला,युवा और वंचित वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं संचालित की हैं,जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्ज्वला योजना,आयुष्मान भारत,स्वच्छ भारत मिशन,हर घर जल योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जनधन योजना जैसी योजनाओं ने आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। इन योजनाओं के माध्यम से विकास की किरण देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची है,उज्ज्वल दीपक ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को भी नई पहचान दिलाई है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय आदिवासी समाज के सम्मान का प्रतीक है, वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नया संसद भवन,सेंगोल की स्थापना और विभिन्न राष्ट्रीय स्मारकों का निर्माण देश की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने वाले कदम हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया है। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री अभियान के माध्यम से विभिन्न देशों को सहायता प्रदान कर भारत ने मानवता की सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया,आज विश्व भारत को समाधान प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र के रूप में देख रहा है,जी-20 की सफल अध्यक्षता, विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापारिक समझौते और बढ़ते विदेशी निवेश भारत की वैश्विक साख को दर्शाते हैं,प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल','फिट इंडिया मूवमेंट','हर घर तिरंगा','जनता कर्फ्यू' और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों ने जनभागीदारी को नई दिशा दी है,इन अभियानों के माध्यम से राष्ट्रहित, सामाजिक उत्तरदायित्व और जनसहभागिता की भावना को बल मिला है,उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं,ताकि आम जनता विकास यात्रा से सीधे जुड़ सके,प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष चम्पा देवी पावले,जिला महामंत्री आशीष मजूमदार,जिला उपाध्यक्ष आशीष सिंह,जिला प्रवक्ता जमुना पाण्डेय, जिला मीडिया प्रभारी रामचरित द्विवेदी,कार्यालय मंत्री राजेश यादव, युवा मोर्चा के आनंद ताम्रकार सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

CMYK

अमिताभ बच्चन की ये फिल्म देख खूब रोये लोग,4 दिन रही फ्लॉप,फिर छप्पड़फाड़ कमाई कर हिला डाला था बॉक्स ऑफिस

अमिताभ बच्चन की एक फिल्म शुरू में थिएटर्स में नहीं चली थी,लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के करियर में भी काफी उतार-चढ़ाव आए। कभी सिनेमा में सिर्फ उनका ही दबदबा रहा और कभी उनकी फिल्में धड़ाम से नीचे गिरती रहीं। 2000 के दशक में भी ऐसा ही था। अमिताभ बच्चन की फिल्में नहीं चल रही थीं। उनके करियर का ग्राफ नीचे जा रहा था, तभी उनके हाथ एक ऐसी फिल्म आई जिसने फिर से उनकी किस्मत चमका दी। मगर इस फिल्म की रिलीज में भी खूब अड़चन आई। डिस्ट्रीब्यूटर तो फिल्म लेने से ही इनकार करने लगे थे। यहां तक कि शुरू के चार दिन तो थिएटर्स ऑडियंस के लिए तरस गई थी।

फिल्म देख इमोशनल हो जाती थी ऑडियंस

अमिताभ बच्चन की ये फिल्म थी 2003 में रिलीज हुई बागबान । रवि चोपड़ा

निर्देशित इमोशनल फैमिली ड्रामा बागबान की कहानी एक ऐसे माता-पिता की है जिन्हें उनके बच्चे अलग कर देते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। फिल्म आज भी दर्शकों के आंखों में आंसू ला देती है। उस दौर में भी सिनेमाघरों में दर्शक इस फिल्म को देख खूब रोए थे।

शुरू के चार दिन फ्लॉप रही थी फिल्म

एक बार रवि चोपड़ा की पत्नी रेणु चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बागबान को लेकर एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि यह फिल्म शुरू के चार दिनों बिल्कुल नहीं चली थी। फिल्म के डायरेक्टर रवि सोचने लगे थे कि आखिर उन्होंने यह फिल्म क्यों ही बनाई।

सलमान को कास्ट करने की मिली थी सलाह

सिर्फ इतना ही नहीं,जब बागबान बनकर तैयार हो गई थी, तब कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म लेने के लिए तैयार ही नहीं था। लोग इस फिल्म को ओल्ड फैशन बता रहे थे। अमिताभ का करियर भी ठीक नहीं चल रहा था। तब किसी ने डायरेक्टर को सलाह दी कि फिल्म में सलमान खान को गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर ले लो। फिर रवि उनसे मिलने गए और सलमान तुरंत यह फिल्म करने के लिए मान गए।
बागबान सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। करीब 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ के पार कारोबार किया था।

बिहार के लोकगीतों को मिला राष्ट्रीय मंच

साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म 'मैंने प्यार किया' आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म से सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसी फिल्म के साथ एक ऐसी गायिका ने भी अपनी अलग पहचान बनाई,जिन्होंने भारतीय लोक संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की,जिनकी आवाज ने इस फिल्म के एक लोकप्रिय गीत 'कहे तोसे सजना' को खास पहचान दी। यह गाना उस समय दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है। कम लोगों को यह

जानकारी है कि यह गीत किसी ओरिजिनल फिल्मी रचना पर आधारित नहीं था, बल्कि यह बिहार के पारंपरिक लोकगीत से प्रेरित था। शारदा सिन्हा ने अपनी सुरीली आवाज के जरिए इस लोकगीत को फिल्मी संगीत के साथ जोड़कर इसे एक नया जीवन दिया। इस गीत की लोकप्रियता के बाद शारदा सिन्हा को भारतीय लोक संगीत को मुख्यधारा में लाने का श्रेय दिया जाने लगा। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे लोकगीत गाए, जिनमें बिहार और पूर्वी भारत की संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 'मैंने प्यार किया' जैसी फिल्मों में लोक संगीत का इस्तेमाल न केवल गानों को लोकप्रिय बनाता है, बल्कि क्षेत्रीय संस्कृति को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद करता है। शारदा सिन्हा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी गायकी ने यह साबित किया कि लोक संगीत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आज के दौर में भी उतना ही प्रभावशाली और लोकप्रिय हो सकता है। आज भी 'कहे तोसे सजना' जैसे गीत भारतीय संगीत प्रेमियों के बीच उतने ही पसंद किए जाते हैं और यह शारदा सिन्हा की अमिट पहचान का हिस्सा बन चुके हैं।

अलका याग्निक की निजी जिंदगी को लेकर चर्चा

दशकों तक बॉलीवुड संगीत जगत पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने वालीं दिग्गज गायिका अलका याग्निक अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उनके पति नीरज कपूर को लेकर एक बार फिर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। जानकारी के अनुसार अलका याग्निक ने वर्ष 1989 में बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की थी। दोनों की शादी को अब 36 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह कपल एक-दूसरे से अलग रहता है। हालांकि यह सुनने में चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन दोनों के बीच किसी तरह के मनमुटाव या तलाक की स्थिति नहीं है।
बताया जाता है कि अलका याग्निक और नीरज कपूर अपने-अपने करियर और जिम्मेदारियों के कारण अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं। अलका याग्निक अपने संगीत करियर और काम की व्यस्तता के चलते अधिकतर मुंबई में रहती हैं,जबकि नीरज कपूर अपने व्यवसाय से जुड़े कार्यों के कारण अलग जगह पर समय बिताते हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं और वे समय-समय पर एक-दूसरे से मिलते रहते हैं। दोनों की यह जीवनशैली व्यक्तिगत स्वतंत्रता और करियर प्राथमिकताओं पर आधारित मानी जाती है।
संगीत जगत में अलका याग्निक का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कई दशकों तक हजारों हिट गानों में अपनी आवाज दी है और आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उनकी निजी जिंदगी को लेकर भले ही लोगों में उत्सुकता रहती हो,लेकिन वे हमेशा अपने काम और संगीत पर ध्यान केंद्रित करती आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक अलग तरह का वैवाहिक संतुलन है, जिसमें दोनों अपने-अपने जीवन और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हुए भी रिश्ते को बनाए रखते हैं।

संचिता उगाले मामले में सुशांत सिंह राजपूत कनेक्शन पर भाई का बयान

दिवंगत एक्ट्रेस संचिता उगले के भाई आकाश सतीश उगले ने अपनी बहन के सुसाइड और 2020 में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बीच कनेक्शन होने का आरोप लगाया है। एक खास बातचीत में, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी बहन और सुशांत दोनों पर इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इतना ही नहीं, दोनों की मौत एक ही तारीख को हुई,यानी 6 साल के अंतर पर। उन्होंने बताया कि संचिता उगले के सोशल मीडिया हैंडल पर आखिरी पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में थी। उन्होंने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की थी जिसमें लिखा था–आज फिर 14 जून है, रविवार को सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए। आकाश ने बताया, उसने 14 जून 2020 को सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड, इस इंडस्ट्री ने उस पर बहुत प्रेशर डाला, और उसी प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ठीक वैसे ही, कल मेरी बहन ने भी इसी वजह से सुसाइड कर लिया, यही मैं कह रहा हूँ। 6 साल के गैप पर हुई दोनों अचानक मौतों के बीच कनेक्शन बताते हुए,उसने कहा, बस 1 दिन पहले, मतलब कल, उसने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की जिसमें लिखा था–इट्स अगेन 14 जून। इसका मतलब है कि 14 जून फिर से हो रहा है और कल ही उसने भी सुसाइड कर लिया।

आपकी याद आती है...सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुई भूमि पेडनेकर

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज छठी डेथ एनिवर्सरी है और उन्हें याद करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इमोशनल हो गईं।
भूमि पेडेनकर और सुशांत सिंह राजपूत ने साथ में फिल्म सोनचिड़िया में काम किया था, जिसका निर्देशन अभिषेक चौबे ने किया था। यह फिल्म अभिनेता के निधन से ठीक एक साल पहले रिलीज हुई थी जो भले ही सफल न हो सकी लेकिन इसे पॉजिटिव रिव्यू मिले थे।

भूमि को आई सुशांत की याद

आज सुशांत सिंह की डेथ एनिवर्सरी पर भूमि पेडनेकर को अपने को-स्टार की याद आई और उन्होंने सोनचिड़िया फिल्म की मेमोरी शेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने फिल्म के सेट से एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- आपकी याद आती है। क्या कमाल का टैलेंट, क्या बेहतरीन एक्टर। एक जटिल सोच वाले इंसान, जो दिलचस्प, जिंदादिल और जीनियस थे। यह तस्वीर %सोनचिड़िया% के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान ली गई थी। कितनी शानदार यादें हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में

सोनचिड़िया, सुशांत की आखिरी फिल्मों में से एक थी। उन्होंने इसके बाद फिल्म ड्राइव की थी। यह भी फ्लॉप रही थी। अभिनेता के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा आई थी जो सीधे ओटीटी पर रिलीज की गई थी। पवित्र रिश्ता से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और 12 फिल्मों के जरिए हमेशा-हमेशा के लिए फैंस के दिलों में बस गए।

खेल समाचार

डब्ल्यूएफआई ने बाकू में होने वाली यू-17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पूरी भारतीय टीम की घोषणा की

नई दिल्ली,15 जून 2026। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने सोमवार को आने वाली यू-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए पूरी इंडियन टीम की घोषणा की। यह चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक अज़रबैजान के बाकू में होगी। सोनीपत और लखनऊ में तीनों डिसिप्लिन में बहुत कड़े नेशनल सिलेक्शन ट्रायल के बाद फाइनल टीम को ऑफिशियली चुना गया,जिससे यह पक्का हुआ कि देश के सबसे होनहार युवा एथलीट ग्लोबल स्टेज पर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए चुने गए हैं। नई चुनी गई टीम भारत के शानदार प्रदर्शन को जारी रखने और जूनियर रेसलिंग में ग्लोबल हैवीवेट के तौर पर देश का रुतबा मजबूत करने के लिए बाकू जाएगी।

इंडियन टीम यू-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दो बहुत ही शानदार इंटरनेशनल कैंपेन के बाद आई है, जिसमें पिछले दो एडिशन में विमेंस रेसलिंग टीम सबसे आगे रही थी। स्क्वॉड सिलेक्शन पर बात करते हुए,डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट संजय कुमार सिंह ने कहा, इन ट्रायल्स ने हमारे जूनियर रेसलिंग इकोसिस्टम की ज़बरदस्त गहराई दिखाई है। पूरी तरह से फेयर और कड़े मुकाबले वाले सिलेक्शन प्रोसेस को पक्का करके, हमने देश के सबसे अच्छे युवा टैलेंट की पहचान की है। मुझे यकीन है कि यह लड़ाई के लिए तैयार स्क्वॉड शानदार नतीजे देगी और बाकू में भारत का नाम रोशन करेगी।
विमेंस रेसलिंग डिवीजन में, सिलेक्शन ट्रायल्स में हरियाणा के पहलवानों की ज़बरदस्त टेक्निकल तेज़ी देखी गई, जिन्होंने दस में से छह वेट कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जिसमें दीक्षा (43किग्रा) और गरिमा (73किग्रा) के दमदार प्रदर्शन ने खास जगह बनाई। दिल्ली की टीम ने कामना बबल (49किग्रा) और अक्षरा (53किग्रा) के ज़रिए दो जगह पक्की की, जबकि महाराष्ट्र की रोहिणी खानू देवबा (36-40किग्रा) और राजस्थान की संध्या (46किग्रा) ने शुरुआती स्क्वॉड पोजीशन हासिल कीं।
मेन्स फ्रीस्टाइल ब्रैकेट्स में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें हरियाणा के बेहतरीन एथलीट जैसे सतिंदर (60किग्रा) और आरुष राणा (110किग्रा) ने अपने-अपने डिवीजन जीते। उत्तर प्रदेश ने आर्यन (48किग्रा) और दीपांशु खोखर (80किग्रा) के ज़रिए दो वेट क्लास हासिल कीं, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली और डब्ल्यूएफ आई के इंडिविजुअल एथलीट्स ने एक-एक कैटेगरी जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की की। ग्रीको-रोमन डिसिप्लिन में महाराष्ट्र के ग्रैपलर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जिन्होंने सचिन शिरोले (45किग्रा) और राजवर्धन पाटिल (92किग्रा) समेत पाँच टॉप स्पॉट हासिल किए। उत्तर प्रदेश ने दो और स्पॉट जोड़े, जबकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के एथलीट्स ने एक-एक टॉप फिनिश हासिल करके टीम के अज़रबैजान जाने से पहले नेशनल रोस्टर पूरा किया।

ओरिएंटल कप का चौथा संस्करण लौटेगा

स्कूल फुटबॉल विकास पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली,15 जून 2026। ओरिएंटल कप,दिल्ली-के सबसे तेज़ी से बढ़ते स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। यह इस साल के आखिर में अपने चौथे एडिशन के साथ वापस आने वाला है। इसका मकसद युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को खेल के लिए अपना टैलेंट और पैशन दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देना है। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक,स्टूडेंट-एथलीट फरीद बख्शी ने 2023 में ओरिएंटल कप शुरू किया था। इसने दिल्ली के स्कूल स्पोर्ट्स कैलेंडर में तेज़ी से अपनी जगह बना ली है।
पिछले तीन एडिशन में, इस टूर्नामेंट ने पूरे इलाके के बड़े स्कूलों के सैकड़ों स्टूडेंट-एथलीट को एक साथ लाया है, जिससे फुटबॉल के ज़रिए खेल में बेहतरीन प्रदर्शन, टीम वर्क और कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा मिला है। सबसे नया एडिशन, जो जुलाई 2025 में मशहूर डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में हुआ था, उसमें लड़कों और लड़कियों की कैटेगरी की 36 स्कूल टीमों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम, लड़कों की कैटेगरी में चैंपियन बना, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फरीदाबाद ने लड़कियों का टाइटल जीता। इस टूर्नामेंट ने पिछले सालों में एयर फ़ोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, एपेक्स स्कूल और दो बार

की गर्ल्स चैंपियन संस्कृति स्कूल जैसे जाने-माने चैंपियन भी बनाए हैं, जो इस इलाके में स्कूल फुटबॉल की बढ़ती कॉम्पिटिशन और गहराई को दिखाता है। पिछले तीन सालों में टूर्नामेंट की लगातार ग्रोथ ने इसे दिल्ली-में स्कूल फुटबॉल के लिए एक जाना-माना प्लेटफ़ॉर्म बनाने में मदद की है, जिसने बड़े इंस्टीट्यूशन्स से पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट किया है, साथ ही ग्रासरूट लेवल पर प्लेयर डेवलपमेंट पर भी ज़ोर दिया है। टूर्नामेंट की वापसी की घोषणा करते हुए, को-फ़ाउंडर फ़रीद बख्शी ने कहा,स्कूल फुटबॉलर्स के लिए ज़्यादा मौके बनाने के आइडिया के तौर पर जो शुरू हुआ था, वह एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में बदल गया है जो पूरे इलाके के युवा एथलीट्स,स्कूलों, कोचों और सपोर्टर्स को एक साथ लाता है।

अल्वारेज़ डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई बुल्स के कप्तान होंगे

चेन्नई,15 जून 2026। अर्जेंटीना के पावरहाउस,सैंटियागो अल्वारेज़ को रग्बी प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन, चेन्नई बुल्स का कैप्टन बनाया गया है। वह पुरुषों की टीम को लीड करेंगे, जबकि भारतीय सुपरस्टार मोहित खत्री को वाइस कैप्टन बनाया गया है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, चेन्नई बुल्स 16 जून को हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में दिल्ली रेड्ज़ के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेंगे। महिला लीग के पहले सीज़न में चेन्नई बुल्स की महिला टीम को चैंटेल मिएल लीड करेंगी, और सवाना बाउडर वाइस-कैप्टन होंगी। वे 16 जून को महिलाओं के लिए पहले मैच में दिल्ली रेड्ज़ के खिलाफ अपने कैप्टेन की शुरुआत करेंगी। सैंटियागो अल्वारेज़ ने कहा, इस सीज़न में चेन्नई बुल्स को लीड करना गर्व की बात है, और मुझे उम्मीद है कि हम सीज़न 1 से अपना टाइटल बचा पाएंगे। बुल्स जैसी अलग-अलग तरह की टीम को लीड करना एक रोमांचक चैलेंज है, और मुझे खुशी है कि मोहित खत्री वाइस-कैप्टन के तौर पर मेरे साथ हैं।

बीएलडब्ल्यू वाराणसी में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए तैयार

वाराणसी,15 जून 2026। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो इंडियन रेलवे की एक बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है, 16 से 18 जून तक वाराणसी में अपने गोल्फ कोर्स में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन गोल्फ टूर्नामेंट 2026 होस्ट करने के लिए तैयार है।इस नेशनल लेवल के टूर्नामेंट से उम्मीद है किबीएलडब्ल्यू जिसे बरेका के नाम से जाना जाता है, भारत के प्रोफेशनल गोल्फ मैप पर मजबूती से अपनी जगह बनाएगा, साथ ही वाराणसी को बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पर और मजबूत करेगा।

स्पोर्ट्स के माहौल की वजह से, बरेका गोल्फ कोर्स को इस मशहूर कॉम्पिटिशन को होस्ट करने का मौका मिला है। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए इस टूर्नामेंट का मकसद देश के उभरते हुए खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देना है। कॉम्पिटिशन की तैयारियों के तहत, कोर्स सेटअप और फाइनल अरेंजमेंट 13 जून को ही पक्का कर लिए गए थे।प्रो इवेंट 14 जून को ऑर्गनाइज़ किया गया था, जिसमें बरेका के गोल्फर्स और प्रोफेशनल गोल्फर्स की जॉइंट टीमों के बीच 9-होल का कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज़ किया गया था। सोमवार को खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस राउंड होगा,जबकि मेन कॉम्पिटिशन 16 जून से 18 जून 2026 तक खेला जाएगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13-17 जुलाई तक चलेगा

5 बैठकें होंगी, स्कूलों में मंत्र-पाठ और कानून व्यवस्था पर हो सकती है बहस..

रायपुर,15 जून 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना और कार्यसूची जारी कर दी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिनमें प्रश्नोत्तर, शासकीय कार्य और वित्तीय मामलों चर्चा होगी। पहले 4 दिनों तक प्रश्नोत्तर काल और शासकीय कार्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं अंतिम दिन 17 जुलाई को प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्यों के साथ गैर-शासकीय कार्य भी लिए जाएंगे। सदन में स्कूलों में मंत्र-पाठ और कानून व्यवस्था पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है।

योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखेगी सरकार

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था, किसानों, बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न विभागों में हुए विवादित फैसलों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। चूंकि सत्र की अवधि केवल 5 दिन रखी गई है, इसलिए विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी उठ सकती है।

स्कूलों में मंत्र-पाठ के मुद्दे पर हो सकती है बहस

सत्र के दौरान स्कूलों में मंत्र-पाठ के आदेश, कानून-व्यवस्था, हसदेव में जंगल कटाई, शराब दुकानों में ओवररेटिंग, किसानों की समस्याएं, नगरीय निकायों के मुद्दे और विभिन्न विभागों में हालिया विवादों को लेकर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आमने-सामने की स्थिति बन सकती है।

बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य बिल हुआ था पास

इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 पास हुआ था। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बजट सत्र के आखिरी दिन सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल पास हुआ। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बिल 2026 भी पास कर दिया गया है। परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल में अभ्यर्थियों के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं।

परिवहन विभाग में अधिकारियों का तबादला

रायपुर,15 जून 2026। परिवहन विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दो परिवहन अधिकारियों का अस्थायी तबादला किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संयुक्त सचिव परिवहन विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक श्री मृत्युंजय पटेल, जो वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय रायपुर में पदस्थ थे,उन्हें अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं श्री प्रतीक शुक्ला,जो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रूप में क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त कार्यालय में कार्यरत थे, उन्हें जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह स्थानांतरण अस्थायी रूप से किया गया है और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी हुआ है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्र नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। परिवहन विभाग में इस तरह के तबादले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते हैं, जिसके तहत विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से जारी इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरण के बाद भी कार्यों की निरंतरता प्रभावित न हो और जनता से जुड़े परिवहन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बीजेपी नेता पर 90 लाख की संपत्ति हड़पने का आरोप,पीड़ित महिला ने मांगी इच्छामृत्यु

बिलासपुर,15 जून 2026। 87 साल की बुजुर्ग महिला ने इच्छा मृत्यु मांगी है। आरोप है कि भाजपा समर्थित पंच ने केवाईसी, धान-पंजीयन और बीमा के बहाने 90 लाख रुपए की संपत्ति हड़प ली। मामला कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी का है।यह भी आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी पुलिस ने भाजपा समर्थित पंच और रिश्तेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री और अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुजुर्ग महिला का नाम बालकुंवर बसोर है, जो बेलगहना की रहने वाली है। वह पति और तीन बेटों को खो चुकी हैं। बालकुंवर झौवा-टुकनी (बांस की टोकरियां) बेचकर गुजारा करती हैं। उनकी एक बेटी उनके साथ रहती है और देखभाल करती है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि केन्दा निवासी भाजपा समर्थित पंच फगुन प्रसाद प्रजापति उर्फ मोनू ने मजबूरी का फायदा उठाया। उसने बैंक में केवाईसी कराने और मदद करने का भरोसा दिलाकर उनसे नजदीकी बढ़ाई। आरोप है कि 14 दिसंबर 2021 को उसने धोखे से उनके भारतीय स्टेट बैंक खाते से 23 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत लूफा स्थित खसरा नंबर 763 और 991/2 की करीब 2.5 हेक्टेयर कृषि भूमि भी अपने नाम करा ली। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी घर में रखा सोना-चांदी भी ले गया।

फ्रुटी के पैकेट में मिली फंगस जैसी संदिग्ध वस्तु, बच्ची अस्पताल में भर्ती

स्वास्थ्य विभाग ने दुकान से लिए सैंपल,जांच शुरू

धमतरी,15 जून 2026। जिले के मगरलोड क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। करेलीबड़ी गांव में एक मासूम बच्ची द्वारा खरीदी गई फ्रूटी के पैकेट में फंगस जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है,जहां उसका इलाज जारी है। वहीं, खाद्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बच्ची ने गांव के एक जनरल स्टोर से फ्रूटी खरीदी थी। घर पहुंचकर जब वह जूस पी रही थी,तभी परिजनों की नजर पैकेट के अंदर पड़ी। पैकेट में कोई संदिग्ध वस्तु या फंगस जैसी सामग्री तैरती हुई दिखाई दी। इसे देखकर परिजन घबरा गए और तुरंत बच्ची को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने संबंधित जनरल स्टोर से फ्रूटी के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि संबंधित उत्पाद किस डीलर या थोक विक्रेता के माध्यम से दुकान तक पहुंचा था। इस घटना के बाद खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उनके रखरखाव को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं बाजार में नकली उत्पाद तो नहीं बेचे जा रहे हैं, या फिर उत्पादों के भंडारण और रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पैकेट में फंगस जैसी वस्तु मिलने की शिकायत मिली है।

छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से महंगी होगी बिजली

बिजली वितरण कंपनी ने मांगी थी 24% बढ़ोतरी...

रायपुर,15 जून 2026। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जो आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगी। राहत की बात यह है कि जहां बिजली वितरण कंपनी ने दरों में 24 प्रतिशत की भारी-भरकम बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, वहीं आयोग ने गहन समीक्षा के बाद औसतन केवल 6.23 प्रतिशत की वृद्धि को ही हरी झंडी दिखाई है। बिजली की दरों में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के उपभोक्ता को प्रभावित करेगी, जिसमें घरेलू कनेक्शन, खेती-किसानी और औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। आयोग द्वारा कंपनी के प्रस्तावित 24% के मुकाबले मात्र 6.23% की वृद्धि मंजूर करने से आम जनता और मध्यम वर्ग एक बड़े आर्थिक झटके से बच गया है, हालांकि मासिक बजट में थोड़ा बदलाव तय है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 38,729 मिलियन यूनिट बिजली की बिक्री और 32,520 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था। कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि मौजूदा टैरिफ के हिसाब से उसे 6,304 करोड़ रुपये का बड़ा राजस्व घाटा हो सकता है, इसलिए दरों में बड़ी बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। हालांकि, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव का कड़ा और विस्तृत तकनीकी परीक्षण किया। आयोग ने कंपनी के दावों को खारिज करते हुए बिजली बिक्री का अनुमान बढ़ाकर 39,760 मिलियन यूनिट और वार्षिक राजस्व आवश्यकता को घटाकर 28,348 करोड़ रुपये पर सीमित कर दिया। सबसे बड़ी राहत यह रही कि आयोग ने कंपनी के 6,304 करोड़ रुपये के घाटे के दावे को घटाकर महज 1,662 करोड़ रुपये मान्य किया, जिससे टैरिफ की दरें नियंत्रण में रहीं। नियामक आयोग के नए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के भीतर प्रति यूनिट बिजली की औसत आपूर्ति लागत 7.13 रुपये निर्धारित की गई है। इसके मुकाबले मौजूदा टैरिफ के आधार पर औसत बिलिंग दर 6.71 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है, जो कि वास्तविक लागत से 42 पैसे कम है। इसी 42 पैसे के अंतर (राजस्व घाटे) को पाटने के लिए विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में औसतन 6.23 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस नए बदलाव का असर अब छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि क्षेत्र और भारी तथा लघु उद्योगों के आगामी बिलों में साफ नजर आएगा।

चलती कार बनी आग का गोला,परिवार के तीन लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान,हाईवे पर मची अफरा-तफरी...

दुर्ग,15 जून 2026। जिले में एक बड़ा हादसा टल गया, जब बायपास रोड पर दौड़ रही एक कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। कार में सवार एक ही परिवार के तीन लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, परिवार कार से बायपास रोड होते हुए दुर्ग की ओर जा रहा था। इसी दौरान कार के अगले हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते वाहन आग की चपेट में आ गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कार में सवार सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में कार आग का गोला बन गई और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार का अगला हिस्सा धू-धू कर जलता दिखाई दे रहा है। वाहन से उठता काला धुआं दूर तक नजर आ रहा है, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

नहीं रहा छत्तीसगढ़ का टूरा भोको लोलो...रैपर एपी राजा का निधन

रायपुर,15 जून 2026। छत्तीसगढ़ी संगीत जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। प्रदेश के लोकप्रिय रैपर चेतन चांडक उर्फ एपी राजा का रायपुर स्थित अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सामने आते ही संगीत जगत, प्रशंसकों और कलाकारों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। एपी राजा का जीवन संघर्ष और मेहनत की एक ऐसी कहानी है, जिसमें कठिन परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया और रैप म्यूजिक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जन्म वर्ष 1994 में नवागढ़ में हुआ था। उनके माता-पिता मूल रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले के रहने वाले थे, जो बाद में रोजगार और जीवनयापन के कारण छत्तीसगढ़ के बेमेतरा और फिर नवागढ़ में आकर बस गए। एपी राजा ने अपने बचपन के शुरुआती वर्ष दुर्ग में बिताए, जहां से उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 2002 के आसपास उनका परिवार भानुप्रतापपुर (कांकेर) में जाकर बस गया। यहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा और रोजाना भानुप्रतापपुर से कांकेर तक यात्रा करके शिक्षा प्राप्त करते थे। कांकेर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही एपी राजा ने रचनात्मकता की दिशा में कदम बढ़ाया। कक्षा 7वीं में उन्होंने अपना पहला रैप लिखा, जिसने उनके संगीत के प्रति झुकाव को दर्शाया। समय के साथ उनका रुझान रैप और म्यूजिक की ओर बढ़ता गया। हालांकि जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं थीं।

11वीं कक्षा के दौरान उनके पिता को हार्ट अटैक आया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। इस कठिन समय में परिवार की जिम्मेदारी बढ़ने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी।

नए शैक्षणिक सत्र 2026 को लेकर मुख्यमंत्री साय का विद्यार्थियों को संदेश

रायपुर,15 जून 2026। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 जून से 27 जून 2026 तक आयोजित होने वाले 'शाला प्रवेश उत्सव' में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त आधार है तथा यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री साय ने अपने पत्र में प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र के साथ प्रदेशभर में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बालक-बालिका का विद्यालय में प्रवेश तथा नियमित अध्ययन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, महापौर तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र के किसी विद्यालय में सुविधानुसार उपस्थित होकर अभियान में सहभागी बनें तथा ऐसे बच्चों की पहचान और नामांकन के लिए प्रेरित करें, जो अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सहभागिता इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री साय ने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण विकसित किया जा रहा है तथा वर्ष 2026 से 150 विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शासकीय विद्यालयों को आधुनिक, तकनीक-संपन्न और छात्र-केंद्रित संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश तथा बालिकाओं के लिए सरस्वती साइकिल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग और व्यापक जनभागीदारी से शाला प्रवेश उत्सव को सफल बनाते हुए प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

कलेक्टर के एक्शन से मचा हड़कंप,10 हजार की घूस लेते पकड़ाई बैंक मैनेजर...

रायपुर,15 जून 2026। जिला सहकारी बैंक की एक महिला मैनेजर की मनमानी का मामला सामने आया है। मृतक के नॉमिनी से 10 हजार की घूस मांगना मैनेजर को भारी पड़ गया, कलेक्टर के आदेश पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। निपानिया की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में प्रभारी मैनेजर के पद पर तैनात अनीता पाण्डेय के खिलाफ कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची थी। इस शिकायत ने बैंक के अंदर चल रही धांधली की पोल खोलकर रख दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि बैंक में मृतक खातेदार के नॉमिनी से राशि के भुगतान के बदले घूस की मांग की गई थी। अनीता पाण्डेय ने काम निकालने के नाम पर सीधे 10,000 रुपये रिश्वत मांगे थे। पीड़ित ने चुप बैठने के बजाय हिम्मत दिखाई और सीधे कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंच गया। शिकायत मिलते ही कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत जांच के लिए नोडल अधिकारी को तैनात किया। जब जांच रिपोर्ट आई, तो मैनेजर पर लगे आरोप पूरी तरह सच साबित हुए।

रामकृष्ण हॉस्पिटल में हो सकेगा पत्रकारों का रियायती दर पर इलाज

रायपुर,15 जून 2026। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के तत्वावधान में रायपुर प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्यों, पत्रकार साथियों एवं उनके परिजनों के लिए आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का 'आभार एवं समापन समारोह' आज रविवार को रायपुर प्रेस क्लब, मोती बाग में गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल, रायपुर द्वारा आयोजित इस शिविर के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप दवे उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश थोरानी ने की। इस दौरान रायपुर प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद थे।

पत्रकारों के लिए हमेशा रहेगी विशेष छूट : डॉ. संदीप दवे ने पत्रकार जगत को एक और बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि शिविर समाप्त होने के बाद भी रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए विशेष रियायतें जारी रहेंगी। इसके तहत निःशुल्क ओपीडी की सुविधा मिलेगी। दवाइयों पर 10% की छूट प्रदान की जाएगी। हॉस्पिटल चार्ज (अस्पताल के अन्य शुल्कों) में 30% की स्थायी छूट हमेशा लागू रहेगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी और रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने इस मानवीय पहल के लिए रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉ. संदीप दवे का आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि इस शिविर से सैकड़ों पत्रकार परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिला है और भविष्य में मिलने वाली छूट से उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी। समारोह के अंत में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा सफल आयोजन के लिए सभी सम्माननीय अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह सलूजा एवं राधा कृष्ण सुंदरानी के अलावा कार्यक्रम संयोजक अमर गीदवानी, के साथ कार्यक्रम समन्वयक अनिल जोतसिंघानी और चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रमुख पदाधिकारी गण मौजूद रहे एवं कार्यक्रम में प्रेस क्लब के महासचिव गौरव शर्मा भारतीय,उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा,प्रशांत शर्मा,संदीप पुराणिक,ताहिर हैदरी, प्रदीप दुबे, विजय शर्मा , विद्या भूषण सिन्हा, रमेश पांडेय,प्रत्यूष शर्मा एवं पत्रकारगण उपस्थित थे।

शिविर की अवधि 30 जून तक बढ़ी,कूपन धारकों को राहत

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. संदीप दवे ने पत्रकारों की सामाजिक सहभागिता और उनके कठिन कार्य परिवेश की सराहना की। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारों और उनके परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर की अवधि को अब 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। पूर्व में पत्रकारों को जारी किए गए कूपन के माध्यम से वे इस विस्तारित अवधि तक अपनी निशुल्क जाँचें करवा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में 759 एल्डरमैन पद खाली : भाजपा कार्यकर्ताओं को है इंतजार,विपक्ष का वार-आर्थिक बोझ से डर रही सरकार

रायपुर,15 जून 2026। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति नहीं हो सकी है। राज्य के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बड़ी संख्या में ये पद खाली पड़े हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस शासनकाल में नियुक्त किए गए एल्डरमैनों को हटाए जाने के बाद से प्रदेशभर के निकायों में ये पद रिक्त हैं। इसके बाद नई नियुक्तियों को लेकर भाजपा सरकार की ओर से अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। एल्डरमैन नियुक्ति को भाजपा संगठन के लिए भी अहम माना जा रहा है। लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता इन पदों पर जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि सरकार सामाजिक,राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन कर सकती है। प्रदेश में करीब 194 नगरीय निकाय हैं, जिनमें नगर निगम,नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल हैं। नियमों के अनुसार इन निकायों में निर्धारित संख्या में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे कुल संभावित नियुक्तियों का आंकड़ा 700 से अधिक पहुंच सकता है।

कांग्रेस और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप : एल्डरमैन नियुक्ति में देरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार आर्थिक बोझ और अंदरूनी खींचतान के कारण फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और पार्टी के योग्य एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।

सिर्फ राजनीतिक पद नहीं,परिषद में भी अहम भूमिका : एल्डरमैन का पद केवल राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नगरीय प्रशासन में भी इसकी भूमिका मानी जाती है। विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को निकायों से जोड़ने का उद्देश्य स्थानीय विकास योजनाओं में सहयोग लेना होता है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)